RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 03, अंक 10 मासिक पत्रिका
25 अक्टूबर 2024

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

राजनीति आरएसएस की प्राथमिकता में नहीं है...

TATA AIA लाइफ इंश्योरेंस के रीवा क्लस्टर के अंतर्गत रीवा मै हुए भव्य कार्यक्रम में ग्वालियर से सुनील कौशिक और मनोज चतुर्वेदी हुए अवॉर्ड से सम्मानित। इस कार्यक्रम में ग्वालियर टाटा एआईए ब्रांच का प्रतिनिधित्व नवीन जैन और अनिल शर्मा ब्रांच मैनेजर ने किया। इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इस कार्यक्रम में जीवन में जीवन बीमा का क्या महत्व है और क्यों जरूरी है इस पर प्रकाश डाला इसी क्रम में राजेश वर्मा एडीओए ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरुण कुमार हेड ऑफ एजेंसी तथा संजय मेहरा डायेक्टर ऑफ एजेंसी उपस्थित थे। इस कार्य में शामिल अधिकारियों ने भी में जीवन बीमा के प्रति जागरूक करते हुए संबोधित किया। इसमें देवाशीष पाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

हमारा देश
हमाराअभिमान

25 अक्टूबर 2024

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडों कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल
- श्री मधु सुदन मिश्रा
- राजेश कुमार त्रिपाठी

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार
- रविकांत शर्मा

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया
- हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर
- सुनील
- हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी ।
(सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	.....	02
शुभाशीष	.....	03
कवर स्टोरी	.....	04-05
देश	.....	06-07
डेंगू	.....	08
वित्त	.....	09
देश	.....	10-11
उज्जैन	.....	12
देश	.....	13
राजनीति	.....	14-15
देश-विदेश	.....	16
देश	.....	17
देश	.....	18
हमारा ग्वालियर	.....	19
इन्दौर	.....	20
कृषि	.....	21
हमारा ग्वालियर	.....	24-45
देश	.....	26
प्रदेश	.....	27
राजस्थान	.....	30
देश	.....	32-33
देश	.....	36-37
देश	.....	38-39
धर्म	.....	42-43
स्वास्थ्य	.....	44
खेल	.....	45
ग्लैमर	.....	47-48

48

शनाया डेब्यू का इंतजार खत्म, विक्रांत के साथ इस फिल्म से मचाएंगी धमाल

संपादकीय

वैश्विक स्तर पर बदल रहे राजनैतिक एवं रणनीतिक समीकरण

भारत की नीतियों के चलते भारत के विचारों को विश्व के समस्त देश अब गम्भीरता से लेने लगे हैं। भारत वैसे भी विश्व मित्र की भूमिका का निर्वहन करना चाहता है। भारत के आज विश्व के समस्त प्रभावशाली देशों के साथ प्रगाढ़ सम्बंध है।

वैश्विक स्तर पर आज परिस्थितियां, विशेष रुप से राजनैतिक, रणनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में, तेजी से बदल रही हैं। नए नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी-7, जी-20 एवं नाटो के सामने ब्रिक्स अपने पांव पसारता नजर आ रहा है। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीयन देश अपनी चमक खो रहे हैं। इन देशों को विकसित देश तो कहा ही जाता रहा हैं, साथ ही, वैश्विक स्तर पर कई संगठनों को खड़ा करने में इन देशों की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है और इन संगठनों की मदद से इन देशों का दबदबा भी पूरे विश्व में कायम रहता आया है। यूनाइटेड नेशनस, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, नाटो, फाइव आइज, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, जी-7 एवं जी-20 जैसे अन्य कई संगठनों के माध्यम पूरे विश्व में ही लगभग प्रत्येक क्षेत्र को यह विकसित देश प्रभावित एवं नियंत्रित करते रहे हैं। परंतु, आज दक्षिणी अफ्रीकी उपमहाद्वीप के देशों, मध्य एशिया में अरब देशों एवं भारतीय उपमहाद्वीप स्थित देशों ने उक्त संगठनों में सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए आवाज उठाना शुरु कर दिया है। उक्त वर्णित लगभग समस्त अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना 1900-2000 शताब्दी में की गई थी। इतने लम्बे अंतराल के बाद भी विश्व के अन्य देशों को इन संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान नहीं की गई है। कुल मिलाकर, अमेरिका एवं यूरोपीयन देशों का दबदबा इन संगठनों की स्थापना के बाद से ही लगातार कायम रहा है।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

भारत के मूल में सनातन हिंदू संस्कृति का आधार है...

भारत में प्राचीन काल से पर्यावरण को पर्याप्त महत्व दिया जाता रहा है। देश में नदियां शुद्ध रहती थी वृक्ष घने जंगलों के रुप में रहते थे और पूरा पर्यावरण शुद्ध रहता था। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नदियों को, पहाड़ों को, वृक्षों को एवं धरती को पूजा जाता है।

किसी भी राष्ट्र के मूल में कुछ तत्व निहित होते हैं, जिनके बल पर वह देश आगे बढ़ता है और समाज के विभिन्न वर्गों को एकता के सूत्र में पिरोए रखता है। भारत के एक राष्ट्र के रुप में, इसके मूल में, सनातन हिंदू संस्कृति का आधार है जो हजारों वर्षों से भारत को आज भी भारत के मूल रुप में ही जीवित रखे हुए है। अन्यथा, पिछले लगभग 1000 वर्षों में भारत को तोड़ने के लिए अरब के आक्रांताओं और अंग्रेजो द्वारा अनेकानेक प्रयास किए गए हैं। अरब के आक्रांताओं एवं अंग्रेजों ने बहुत अधिक प्रयास किए कि किसी तरह भारतीय मूल संस्कृति को तहस नहस किया जाय, शिक्षा पद्धति को ध्वस्त किया जाय, बलात हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाय, आदि आदि। इन प्रयासों में उन्हें कुछ सफलता तो अवश्य मिली परंतु पूर्ण रुप से भारतीय संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाए। जबकि कई अन्य देशों (ईरान, लेबनान, इंडोनेशिया, मिस्त्र, ग्रीक आदि) में इनके यही प्रयास पूर्ण रुप से सफल रहे एवं वहां के लगभग सम्पूर्ण नागरिकों को इस्लाम में परिवर्तित करने में वे सफल रहे। भारत में चूंकि सनातन हिंदू धर्म का बोलबाला है अतः यहां इन तत्वों को आज तक सफलता नहीं मिली है, हालांकि इनके प्रयास अभी भी जारी हैं। भारतीय सनातन संस्कृति ने न केवल भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है बल्कि पूरे विश्व को ही भारत के साथ जोड़ा है। अब तो भारत में 'एक भारत - श्रेष्ठ भारत' के रुप में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जा रहा है।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

राजनीति आरएसएस की प्राथमिकता में नहीं है...

जनसंघ को मजबूत करने में संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख, बलराज मधोक, भाई महावीर, सुंदरसिंह भण्डारी, जगन्नाथराव जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, रामभाऊ गोडबोले, गोपालराव ठाकुर और अटल बिहारी वाजपेयी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दशहरे (12 अक्टूबर, 2024) पर अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने वर्ष 1925 में जो बीज बोया था, आज वह वटवृक्ष बन गया है। उसकी अनेक शाखाएं समाज में सब दूर फैली हुई हैं। संघ लगातार दसों दिशाओं में बढ़ रहा है। 100 वर्ष की अपनी यात्रा में संघ ने समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में राष्ट्रीय भाव का जागरण किया है, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि, आरएसएस विशुद्ध सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन है। इसके बाद भी संघ के संबंध में कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में उसका गहरा प्रभाव है। जब 'संघ और राजनीति' की बात निकलती है तो बहुत दूर तक नहीं जाती। दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निकटता से नहीं जानने वाले लोग इस विषय पर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। राजनीति का जिक्र होने पर संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी को नत्थी कर दिया जाता है। भाजपा, संघ परिवार का हिस्सा है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। लेकिन, भाजपा के कंधे पर सवार होकर संघ राजनीति करता है, यह धारणा बिलकुल गलत है। देश के उत्थान के लिए संघ का अपना एजेंडा है, सिद्धांत हैं, जब राजनीति उससे भटकती है तब संघ समाज से प्राप्त अपने प्रभाव का उपयोग करता है। सरकार चाहे किसी की भी हो। यानी संघ समाज शक्ति के आधार पर राजसत्ता को संयमित करने का प्रयास करता है। अचम्भित करने वाली बात यह है कि कई विद्वान संघ के विराट स्वरूप की अनदेखी करते हुए मात्र यह साबित करने का प्रयास करते हैं कि भाजपा ही संघ है और संघ ही भाजपा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 से 1948 तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के विषय में सोचा भी नहीं था। राजनीति, संघ की प्राथमिकता में आज भी नहीं है। संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार से जब किसी ने पूछा कि संघ क्या करेगा? तब डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया- "संघ व्यक्ति निर्माण करेगा"। अर्थात् संघ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने के लिए ऐसे नागरिकों का निर्माण करेगा, जो अनुशासित, संस्कारित और देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत हों। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब संघ को कुचलने के लिए राजनीति का निर्लज्ज उपयोग किया गया, तब पहली बार यह विचार ध्यान में आया कि संसद में संघ का पक्ष रखने वाला कोई राजनीतिक दल भी होना चाहिए। क्योंकि स्वयंसेवकों को बार-बार यह बात कचोट रही थी कि गांधीजी की हत्या के झूठे आरोप लगाकर विरोधियों ने सत्ता की ताकत से जिस प्रकार संघ को कुचलने का

प्रयास किया है, भविष्य में इस तरह फिर से संघ को परेशान किया जा सकता है। राजनीतिक प्रताड़ना के बाद ही इस बहस ने जन्म लिया कि संघ को राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। विचार-मन्थन शुरू हुआ कि आरएसएस स्वयं को राजनीतिक दल में बदल ले यानी राजनीतिक दल बन जाए या राजनीति से पूरी तरह दूर रहे या किसी राजनीतिक दल को सहयोग करे या फिर नया राजनीतिक दल बनाए। स्वयं को राजनीतिक दल में परिवर्तित करने पर संघ का विराट लक्ष्य कहीं छूट जाता। उस समय कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था, जो संघ की विचारधारा के अनुकूल हो। इसलिए किसी दल को सहयोग करने का विचार भी संघ को त्यागना पड़ा। इसी बीच, कांग्रेस की गलत नीतियों से मर्माहत होकर 8 अप्रैल, 1950 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से इस्तीफा देने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के सरसंघचालक श्रीगुरुजी के पास सलाह-मशविरा करने के लिए आए थे। वे नया राजनीतिक दल बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। श्रीगुरुजी से संघ के कुछ कार्यकर्ता लेकर डॉ. मुखर्जी ने अक्टूबर, 1951 में जनसंघ की स्थापना की। वर्ष 1952 के आम चुनाव में जनसंघ ने एक नये राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया।

जनसंघ को मजबूत करने में संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख, बलराज मधोक, भाई महावीर, सुंदरसिंह भण्डारी, जगन्नाथराव जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, रामभाऊ गोडबोले, गोपालराव ठाकुर और अटल बिहारी वाजपेयी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि संघ के कार्यकर्ता ही जनसंघ का संचालन कर रहे थे इसलिए संघ ने जनसंघ को स्वतंत्र छोड़कर दूसरे आयामों पर अधिक ध्यान देना जारी रखा। साल में एक बार दीनदयाल उपाध्याय और श्रीगुरुजी बैठते थे। दीनदयालजी, गुरुजी को जनसंघ के संबंध में जानकारी देते थे। श्रीगुरुजी कुछ आवश्यक सुझाव भी पंडितजी को देते थे। जनसंघ से भाजपा तक आपसी संवाद की यह परम्परा आज तक कायम है। अब इसे कुछ लोग 'संघ की क्लास में भाजपा' कहें, तो यह उनकी अज्ञानता ही है। इस संदर्भ में श्रीगुरुजी के कथन को भी देखना चाहिए। उन्होंने 25 जून, 1956 को 'ऑर्गनाइजर' में लिखा था- "संघ कभी भी किसी राजनीतिक दल का स्वयंसेवी संगठन नहीं बनेगा। जनसंघ और संघ के बीच निकट का संबंध है। दोनों कोई बड़ा निर्णय परामर्श के बिना नहीं करते। लेकिन, इस बात का ध्यान रखते हैं कि दोनों की स्वायत्तता बनी रहे"।

वर्ष 1975 लोकतंत्र के लिए काला अध्याय लेकर आया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लाद दिया। संघ ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। संघ के कार्यकर्ताओं पर आपातकाल में बड़ी क्रूरता से अत्याचार किए गए। इसके बाद भी संघ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल का विरोध करता रहा। वर्ष 1977 में जनता पार्टी का गठन किया गया। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। लेकिन, कम्युनिस्टों ने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी की जनसंघ के नेताओं को जनता पार्टी से बाहर आना पड़ा। सन् 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। आज भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी के नाते देश चला रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र की संप्रभुता के विषयों पर लगातार चिंतन करता रहता है। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल अनेक अवसर पर भारतीय राजनीति को संदेश देने के प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। राष्ट्रीय भाषा-नीति-1958, गोवा आदि का संलग्न प्रांतों में विलय-1964, साम्प्रदायिक दंगे और राष्ट्रीय एकता परिषद-1968, राष्ट्र एक अखण्ड इकाई-1978, विदेशी घुसपैठिये-1984, पूर्वी उत्तरांचल 'इनर लाइन आवश्यक-1987, अलगाववादी षड्यंत्र-1988, आतंकवाद और सरकार की ढुलमुल नीति-1990, सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण न हो-2005 जैसे अनेक प्रस्ताव हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय दिशा से भटकती राजनीति को सचेत किया है। संघ के प्रयत्नों के कारण ही देश में आज समान नागरिक संहिता पर बहस जारी है। वहीं, जम्मू-कश्मीर से स्थायी दिखनेवाली 'अस्थाई' अनुच्छेद-370 एवं 35ए समाप्त किए जा सके हैं।

भारत और हिन्दू अस्मिता का प्रतीक रामजन्मभूमि का मुद्दा भी संघ की ताकत के कारण ही राजनीतिक बहसों में शामिल हो सका है, जिसका परिणाम आज अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के रूप में हमें दिखायी दे रहा है। चुनाव प्रक्रिया में धन के प्रभाव को रोकने और अपराधियों के चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित कराने के लिए संघ ने सामाजिक अभियान चलाया है। इस संबंध में प्रतिनिधि सभा के वर्ष 1996 के प्रस्ताव को देखना चाहिए, जो राजनीति और भ्रष्टाचार पर केन्द्रित था। वर्तमान में गोहत्या पर बहस छिड़ी हुई है। गौ-संरक्षण के लिए संघ ने अथक प्रयास किए हैं। संघ के आंदोलनों से बने जन दबाव के कारण कांग्रेस सरकारों को भी राज्यों में गोहत्या प्रतिबंध के संबंध में कानून लागू करने पड़े। असम और पश्चिम बंगाल में 1950 में, तत्कालीन बंबई प्रांत में 1954 में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में 1955 में गौहत्या प्रतिबंध संबंधी कानून बनाये गये, उस वक्त वहां कांग्रेस की सरकारें थीं। इसी तरह कांग्रेस के समय में ही तमिलनाडु में 1958 में, मध्यप्रदेश में 1959 में, ओडीसा में 1960 में तो कर्नाटक में 1964 में संबंधित कानूनों को लागू किया गया।

जब कभी भारतीय राजनीति असंतुलित हुई है, संघ ने हस्तक्षेप किया है। अर्थात् सरकारों ने वोटबैंक की राजनीति के फेर में जब-जब राष्ट्रीय एकता के मूल प्रश्न की अनदेखी की है तब-तब संघ ने राजनीति में हस्तक्षेप किया है। भाजपा भले ही संघ परिवार का हिस्सा है, लेकिन संघ ने स्वयं को दलगत राजनीति से हमेशा दूर ही रखा है। देश की सामयिक परिस्थितियों और राजनीति के प्रति संघ सजग रहता है। राजनीति समाज के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। संघ इसी समाज का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। इसलिए संघ और राजनीति का संबंध स्वाभाविक भी है। 'संघ और राजनीति' पुस्तक के लेखक एवं राज्यसभा सांसद प्रो. राकेश सिन्हा कहते हैं- "सांस्कृतिक संगठन का तात्पर्य झाल-मंजीरा बजाने वाला संगठन न होकर राष्ट्रवाद को जीवंत रखने वाला आंदोलन है। इसीलिए आवश्यकतानुसार संघ राजनीति में हस्तक्षेप करता है, जो आवश्यक और अपेक्षित दोनों है"।

हम समझ सकते हैं कि संघ राजनीति का उपयोग इतना भर ही करता है कि उसके मार्ग में बेवजह अड़चन खड़ी न की जाएं। मिथ्या आरोप संघ पर न लगाए जाएं। संघ के पास राजनीतिक शक्ति नहीं है, यह सोचकर कोई उसके वैचारिक आग्रह की अनदेखी न कर सके। एक बात स्पष्टतौर पर समझ लेनी चाहिए कि संघ सीधे चुनाव में भाग नहीं लेता है और भविष्य में भी नहीं लेगा। संघ का राजनीति में प्रभाव अपनी उस ताकत से है, जो अपने 100 वर्ष के कार्यकाल में जनता के भरोसे से हासिल हुई है। देश के खिलाफ कोई ताकत खड़ी होने का प्रयास करती है तब सम्पूर्ण समाज संघ की ओर उम्मीद से देखता है। संकट के समय में भी संघ से ही मदद की अपेक्षा समाज करता है।

भारत और हिन्दू अस्मिता का प्रतीक रामजन्मभूमि का मुद्दा भी संघ की ताकत के कारण ही राजनीतिक बहसों में शामिल हो सका है, जिसका परिणाम आज अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के रूप में हमें दिखायी दे रहा है। चुनाव प्रक्रिया में धन के प्रभाव को रोकने और अपराधियों के चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित कराने के लिए संघ ने सामाजिक अभियान चलाया है।

भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक रोशनी का पर्व है दीपावली

दीपावली का सम्पूर्ण पर्व एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक प्रकार की गति है। एक सत्य से दूसरे सत्य की ओर अनवरत, अनिरुद्ध गति ही दीपावली की जीवंतता है। जीवन के अनेक अनुभवों का समवाय है दीपावली

दीपावली एक समृद्धि, खुशहाली एवं रोशनी का लौकिक पर्व है। यह जितना भौतिक पर्व है, उतना ही आध्यात्मिक पर्व भी है, इसलिये यह केवल बाहरी अंधकार को ही नहीं, बल्कि भीतरी अंधकार को मिटाने का पर्व भी बने। हम भीतर में धर्म का दीप जलाकर मोह और मूर्च्छा के अंधकार को दूर कर सकते हैं। दीपावली के मौके पर सभी आमतौर से अपने घरों की साफ-सफाई, साज-सज्जा और उसे संवारने-निखारने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार अगर भीतर चेतना के आँगन पर जमे कर्म के कचरे को बुहारकर साफ किया जाए, उसे संयम से सजाने-संवारने का प्रयास किया जाए और उसमें आत्मा रूपी दीपक की अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर दिया जाए तो मनुष्य शाश्वत सुख, शांति एवं आनंद को प्राप्त हो सकता है।

दीपावली का सम्पूर्ण पर्व एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक प्रकार की गति है। एक सत्य से दूसरे सत्य की ओर अनवरत, अनिरुद्ध गति ही दीपावली की जीवंतता है। जीवन के अनेक अनुभवों का समवाय है दीपावली। एक अनुभूति से दूसरी अनुभूति तक की यात्रा में जो दीपावली के विलक्षण एवं अद्भुत क्षणों की गति है, वही जीवन की वास्तविकता है। जीवन एक यात्रा है, सतत यात्रा। ठीक इसी तरह दीपावली भी एक यात्रा है, एक प्रस्थान है, कुछ नया पाने की, अनूठा करने की। समय बह रहा है, जीवन बीत रहा है। वर्ष पर वर्ष, माह पर माह, दिन पर दिन एवं पलों पर पल बीत रहे हैं, सांसों के घट रीत रहे हैं। इन घटती सांसों को अर्थपूर्ण बनाने, सम्पूर्णता से जी लेने एवं उपयोगी करने का पर्व है दीपावली। वृक्ष भी जीते हैं, पशु-पक्षी भी जीते हैं, परंतु वास्तविक जीवन वे ही जीते हैं, जिनका मन मनन का उपजीवी हो। मननशीलता की संपदा मानव को सहज उपलब्ध है। अपेक्षा है उसका सम्यक् उपयोग और विकास कर जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करें। उजालों का स्वागत करें।

दीपावली की रात भारत भूमि पर आसमान उतर आता है। ज्यों आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, सो उस रात धरा पर दिए टिमटिमाते हैं। चांद से रीती इस रात का हर पक्ष उजला है। अमावस कहकर कोई याद नहीं रखता इसे। इसमें इतना उजास जो है। कहते हैं सूनी राह पर, अकेले द्वार पर, कुएं की तन्हा मेड़ पर और उजाड़ तक में दीप रखने चाहिए। कोई भूले-भटके भी कहीं किसी राह पर निकले, तो उसे अंधेरा न मिले। इस रात हरेक के लिए उजाले जुटा दिए जाते हैं। अब उजालों के इस अपूर्व एवं अलौकिक पर्व की जगर-मगर में दीपों की माटी कम और लट्टूओं वाली बिजली एवं पटाखों का प्रदूषण अधिक है। वक्त के साथ खुशियों का अहसास तो नहीं बदलता, पर उसकी आमद के जरिए अलग हो जाते हैं। दीपावली पर रोशनी का परचम बुलंद किए हौसलेमंद दिए ज्यों तम के सामने डट जाते हैं, वह एक कालजयी ऐलान है विजय का। इस विजय को पाने एवं मोह का अंधकार भगाने के लिए धर्म का दीप जलाना होगा। जहाँ धर्म का सूर्य उदित हो गया, वहाँ का अंधकार टिक नहीं सकता। एक बार अंधकार ने ब्रह्माजी से शिकायत की कि सूरज मेरा पीछा करता है। वह मुझे मिटा देना चाहता है। ब्रह्माजी ने इस बारे में सूरज को बोला तो सूरज ने कहा-मैं अंधकार को जानता तक नहीं, मिटाने की बात तो दूर, आप पहले उसे मेरे सामने उपस्थित करें। मैं उसकी शक्ल-सूरत देखना चाहता हूँ। ब्रह्माजी ने उसे सूरज के सामने आने के लिए कहा तो अंधकार बोला-मैं उसके पास कैसे आ सकता हूँ? अगर आ गया तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

जीवन का वास्तविक उजाला लिबास नहीं है, भोजन नहीं है, भाषा नहीं है और उसकी साधन-सुविधाएं भी नहीं हैं। वास्तविक उजाला तो मनुष्य में व्याप्त उसके आत्मिक गुणों क महक ही है, जो मानवीय बनाते हैं, जिन्हें संवेदना और करुणा के रूप में, दया, सेवा-भावना, परोपकार के रूप में हम देखते हैं। असल में यही गुणवत्ता उजालों की बुनियाद है, नींव हैं जिसपर खड़े होकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाता है। जिनमें इन गुणों की उपस्थिति होती है उनकी गरिमा चिरंजीवी रहती है। समाज में उजाला फैलाने के लिये इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। जिस तरह दीप से दीप जलता है, वैसे ही प्यार देने से प्यार बढ़ता है और समाज में प्यार और इंसानियत रूपी उजालों की आज बहुत जरूरत है।

दीपों की कतारें दीपावली का शाब्दिक अर्थ ही नहीं, वास्तविक अर्थ है। कतारों के लिए निरंतरता जरूरी है। और निरंतरता के लिए नपा-तुला क्रम। दीप जब कतार में होते हैं, तो आनंद का सूचक बन जाते हैं। जैसे कोई मूक उत्सव हो- जगर-मगर उजाले का। उजालों की पंक्तियां उल्लास का द्योतक हैं। दीप होते ही प्रेरक हैं। एक बाती, अंजुरी-भर तेल और राह-भर प्रकाश। जितना सादा दीपावली का दीपक होता है, उससे सादा कुछ नहीं हो सकता। माटी ने ज्यों पक-जमकर, बाती के बीज से ज्योत पल्लवित की हो। यह विजय पताका कार्तिक अमावस्या के अंधेरे की पूरी रात दूर रखती है। दीपावली की रात को हर दीप रोशनी की लहर बनाता है, उजालों के समन्दर में अपना योगदान देता है।

शेक्सपियर की चर्चित पंक्ति है- 'अगर रोशनी पवित्रता का जीवन रक्त है तो विश्व को रोशनीमय कर दो/ जगमगा दो और इसे जी-भरकर बाहुल्यता से प्राप्त करो।' शेक्सपियर ने यह पंक्ति चाहे जिस संदर्भ में कही हो, पर इसका उद्देश्य निश्चित ही पवित्र था और अनेक अर्थों को लिए हुए यह उक्ति सचमुच में जीवन व्यवहार की स्पष्टता के अधिक नजदीक है। दीपावली का पर्व और उससे जुड़े रोशनी के दर्शन का भी यह उद्घोष है। रोशनी! उत्सव का प्रतीक, खुशी के इज़हार करने का प्रतीक है, सफलता का प्रतीत है। अगर हम इस सोच को गहराई में डुबो लें तो ये सूक्तियां हमारे जीवन की रक्त धमनियां बन सकती हैं और उससे उत्तम व्यवहार की रश्मियां प्रस्फुटित हो सकती है। उन रश्मियों की निष्पत्तियां के स्वर होंगे- ''सदा दीपावली संत की आठों पहर आनन्द'', ''घट-घट दीप जले'', ''दीये की लौ सूरज से मिल जाये''।

जीवन के ह्रास और विकास के संवादी सूत्र हैं- अंधकार और प्रकाश। अंधकार स्वभाव नहीं, विभाव है। वह प्रतीक है हमारी वैयक्तिक दुर्बलताओं का, अपाहिज सपनों और संकल्पों का। निराश, निष्क्रिय, निरुद्देश्य जीवन शैली का। स्वीकृत अर्थशून्य सोच का। जीवन मूल्यों के प्रति टूटती निष्ठा का। विधायक चिन्तन, कर्म और आचरण के अभाव का। अब तक उजालों ने ही मनुष्य को अंधेरों से मुक्ति दी है, इन्हीं उजालों के बल पर उसने ज्ञान को अनुभूत किया अर्थात सिद्धांत को व्यावहारिक जीवन में उतारा। यही कारण है कि उसकी हस्ति आजतक नहीं मिटी। उसकी दृष्टि में गुण कोरा ज्ञान नहीं है, गुण कोरा आचरण नहीं है। दोनों का समन्वय है। जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता वही समाज में आदर के योग बनता है।

हम उजालों की वास्तविक पहचान करें, अपने आप को टटोलें, अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि कषायों को दूर करें और उसी मार्ग पर चलें जो मानवता का मार्ग है। हमें समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, वह बार-बार नहीं मिलता। समाज उसी को पूजता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। इसी से गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है-'परहित सरिस धरम नहीं भाई'। स्मरण रहे कि यही उजालों को नमन है और यही उजाला हमारी जीवन की सार्थकता है। जो सच है, जो सही है उसे सिर्फ आंख मूंदकर मान नहीं लेना चाहिए। खुली आंखों से देखना एवं परखना भी चाहिए। प्रमाद टूटता है तब व्यक्ति में प्रतिरोधात्मक शक्ति जागती है। वह बुराइयों को विराम देता है।

मलेरिया से भी गंभीर है डेंगू का दंश

डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में ड्रोन का प्रयोग अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इंदौर में डेंगू मच्छरों को नष्ट करने के लिए ड्रोन के उपयोग का निर्णय किया गया है। देश के अन्य हिस्सों में भी ड्रोन का उपयोग प्रयोग के रुप में किया जाने लगा है।

भारत सहित दुनिया के देशों में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित दुनिया के देश डेंगू को लेकर अब गंभीर हो गए हैं। इसका बड़ा कारण है कि दुनिया के 130 देश डेंगू की जद में आ चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस समय 4 अरब लोग डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं और 2050 तक यह आंकड़ा पांच अरब को पार कर जाएगा। भारत की बात की जाए तो देश के लगभग हर प्रदेश में डेंगू के नित नए केस सामने आ रहे हैं। भले ही यह माना जाता हो कि डेंगू के कारण मौत की दर बहुत कम है और सामान्यतः डेंगू सामान्य पेरासिटामोल और डॉक्टरों के सलाह के अनुसार पेय पदार्थ एलोरा ज्यूस आदि लेने से ठीक हो सकता है। हालांकि कोल्ड ड्रिंक की सलाह नहीं दी जाती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि डेंगू के कारण तेजी से प्लेटरेट में कमी आती है पर विशेषज्ञों का मानना है कि प्लेटरेट से भी ज्यादा गंभीर होता है ब्लड प्रेशर में कमी आना है। प्लेटरेट के साथ ही ब्लडप्रेशर को नियंत्रित रखना जरुरी हो जाता है। यह ध्यान रखना अधिक जरुरी हो जाता है कि ब्लड प्रेशर लो नहीं होना चाहिए। डेंगू का असर सीधे लीवर पर पड़ता है और ब्लड के अंतःस्राव की समस्या हो जाती है। जो अपने आप में गंभीर होती है। उल्टी होने से डिहाईड्रेशन की समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। दरअसल एक समस्या यह है कि डेंगू का पता भी तीन चार दिन बाद पता चलता है। इसलिए सावधानी सबसे बड़ी जरुरी हो जाती है। खैर सबसे अधिक चिंतनीय यह है कि डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन अब अधिक गंभीर हो गया है।विटामिन और फ़ूड सप्लीमेंट खरीदें

गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि इंडोनेसिया में ड्रोन से सर्वे कर मच्छरों के लार्वा की खोज करके नष्ट करने का यह परिणाम रहा है कि डेंगू के मामलों में 70 फीसदी तक कमी आई है। डेंगू से बचाव के लिए डेंगू मच्छर का खात्मा करने वाले एंटीडेंगू मच्छर को दुनिया के करीब 14 देशों में छोड़े जाने का निर्णय किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में एंटीडेंगू मच्छर का सफल प्रयोग किया जा चुका है और ब्राजील में बड़ा केन्द्र बनाते हुए बोल्वाशिया मच्छर का उत्पादन आरंभ कर दिया गया है। हांलाकि किन किन 14 देशों में एंटी डेंगू मच्छरों को छोड़ा जाएगा यह निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अभी किया जाना है। पर एक बात साफ हो चुकी है कि डेंगू पर समय रहते रोक अभियान चलाया जाना आवश्यक है। क्योंकि डेंगू अब किसी देश की सीमा में बंधा नहीं रह गया है। देश दुनिया की सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने डेंगू बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। दरअसल डेंगू की गंभीरता को देखते हुए ही गैर सरकारी वर्ल्ड मास्कीटो प्रोग्राम के तहत एंटीडेंगू मच्छर विकसित किया गया है। 2023 में इंडोनेशिया में इनका प्रयोग किया जा चुका है और इनके प्रभाव से 95 प्रतिशत तक सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।

हालांकि 2011 में आस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में लगातार चार बरसाती सीजन में एंटीडेंगू मच्छर का प्रयोग किया गया और दावा किया गया कि वहां चार बरसातों में एक भी डेंगू का मामला सामने नहीं आया। इन मंच्छर में एक बैक्टिरिया वोल्वाशिया पापीएंटिस डाला गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे बीमारी वाले मच्छरों को वायरस फैलाने से रोकने में सफल होंगे। अब तक के परीक्षणों में यह खरे भी उतरे हैं। डेंगू की भयावहता को इसी से समझा जा सकता है कि 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाने लगा है। इस दिवस के आयोजन के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस जागृत की जाती है। दरअसल डेंगू एडीज एजिप्टी प्रजाती की मादा मच्छर के कारण तेजी से फैलता है। बरसात के दिनों में यह मच्छर तेजी से फैलता है। जमा पानी और गंदगी आदि में डेंगू मच्छर तेजी से बढ़ते हैं। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर तक डेंगू का प्रकोप अधिक रहता है। शुरुआती दो तीन दिन तक तो जांच में पता ही नहीं चलता है। डेंगू में 3 से 7 दिन अधिक गंभीर होते हैं। प्लेटरेट्स में तेजी से गिरावट होती है। हांलाकि डेंगू के कारण मौत तुलनात्मक रुप से कम है पर डेंगू का प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एंटीडेंगू मच्छर शुभ संकेत माने जा सकते हैं।

डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में ड्रोन का प्रयोग अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इंदौर में डेंगू मच्छरों को नष्ट करने के लिए ड्रोन के उपयोग का निर्णय किया गया है। देश के अन्य हिस्सों में भी ड्रोन का उपयोग प्रयोग के रुप में किया जाने लगा है। सवाल साफ है कि डेंगू के प्रकोप को चुनौती के रुप में लेते हुए सरकार को ठोस प्रयास करने होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी और गैरसरकारी सभी संस्थाओं को आगे आना होगा और सबसे अधिक लोगों में अवेयरनेस के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता और सफाई के प्रति चेतना विकसित करनी होगी।

स्वर्ण ऋण के प्रति बढ़ता बढ़ता रुझान

भारत में सामान्यजन के पास स्वर्ण के रूप प्रतिभूति उपलब्ध रहती है अतः स्वर्ण ऋण बहुत अधिक चलन में आ रहा है। विशेष रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण की प्रतिभूति के विरुद्ध स्वर्ण ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास को गति देने हेतु पूंजी की आवश्यकता रहती है। तेज आर्थिक विकास के चलते यदि किसी देश में वित्तीय बचत की दर कम हो तो उसकी पूर्ति ऋण में बढ़ोत्तरी से की जा सकती है। भारत में ऋणः सकल घरेलू अनुपात अन्य विकसित एवं कुछ विकासशील देशों की तुलना में अभी बहुत कम है। परंतु, हाल ही के समय में भारत का सामान्य नागरिक ऋण के महत्व को समझने लगा है एवं भौतिक संपति के निर्माण में अपनी बचत के साथ साथ ऋण का भी अधिक उपयोग करने लगा है। कुछ बैंक सामान्यजन को ऋण प्रदान करने हेतु प्रतिभूति की मांग करते है। भारत में सामान्यजन के पास स्वर्ण के रूप प्रतिभूति उपलब्ध रहती है अतः स्वर्ण ऋण बहुत अधिक चलन में आ रहा है। विशेष रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण की प्रतिभूति के विरुद्ध स्वर्ण ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में तेजी से बढ़ रहे स्वर्ण ऋण के कारणों एवं कारकों का वर्णन इस लेख में किया गया है।

भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में विभिन्न गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा 39,687 करोड़ रुपए के स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए गए थे, स्वीकृत की जाने वाली यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में बढ़कर 62,835 करोड़ रुपए हो गई एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में और आगे बढ़कर 79,218 करोड़ रुपए हो गई। गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में स्वर्ण ऋण के मामले में 26 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर हासिल की है जबकि अन्य प्रकार के ऋणों में इसी अवधि के दौरान औसत वृद्धि दर 12 प्रतिशत की रही है। भारतीय नागरिक स्वर्ण ऋण के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो रहे हैं। आज भारत के विभिन्न गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों एवं विभिन्न बैंकों द्वारा भारी मात्रा में स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं। अगस्त 2024 माह में बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने मिलकर 41 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करते हुए 1.4 लाख करोड़ रुपए के स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए हैं। आज गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कुल ऋण में स्वर्ण ऋण का प्रतिशत में हिस्सा सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पर स्कूटर एवं चार पहिया वाहनों के लिए प्रदान किए गए ऋणों का ऋण हैं, इसके बाद तीसरे स्थान पर व्यक्तिगत ऋण 14 प्रतिशत के भाग के साथ है एवं इसके बाद जाकर गृह ऋण का नम्बर आता है जो कुल ऋण का 10 प्रतिशत भाग है। बैकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वर्ण ऋण पर पूंजी पर्याप्तता सम्बंधी शिथिल नियमों का पालन करना होता है। अन्य प्रकार के ऋणों की तुलना में स्वर्ण ऋण पर जोखिम का भार (रिस्क वेट) तुलनात्मक रूप से कम रहता है। इससे बैंक एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां भी स्वर्ण ऋण प्रदान करने की ओर आकर्षित होते हैं।

यहां स्वाभाविक रूप से प्रशन्न उभरता है कि पिछले लगभग 3 वर्षों के दौरान भारत के नागरिकों में स्वर्ण ऋण के प्रति इतना रुझान क्यों बढ़ा है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण के भंडार बढ़कर 822 मेट्रिक टन से भी अधिक हो गए हैं परंतु विश्व स्वर्ण काउन्सिल के एक अनुमान के अनुसार, भारतीय नागरिकों के पास स्वर्ण के भंडार बढ़कर 25000 टन से भी अधिक के हो गए हैं, जिनकी बाजार कीमत वर्ष 2020 में 109 लाख करोड़ रुपए की थी। भारत में नागरिकों के पास स्वर्ण भंडार विश्व के कुल स्वर्ण भंडार का 11 प्रतिशत है। भारत में प्रतिवर्ष 750 से 800 टन स्वर्ण का आयात होता है और पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में 17,500 टन स्वर्ण का आयात हुआ है और मार्च 2019 से मार्च 2024 के दौरान भारत में स्वर्ण भंडार 40 प्रतिशत से बढ़ गए हैं। दरअसल, भारत में दीपावली (धन तेरस) के शुभ अवसर पर स्वर्ण की खरीद को शुभ माना जाता है एवं मध्यमवर्गीय परिवार भी धन तेरस के दिन स्वर्ण की खरीद प्रति वर्ष करते हैं। इससे भारत के करोड़ों परिवारों के पास स्वर्ण का स्टॉक उपलब्ध रहता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा स्वर्ण ऋण प्रदान करने के सम्बंध में नियमों को बहुत सरल बनाया है एवं अब भारतीय नागरिकों को स्वर्ण के स्टॉक के विरुद्ध ऋण बहुत ही आसान शर्तों पर उपलब्ध होने लगा है। भारत में प्रचिलित परम्पराओं के अनुसार मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा स्वर्ण को बेचना शुभ नहीं माना जाता है जबकि स्वर्ण की खरीद को शुभ माना जाता है। अतः स्वर्ण को बाजार में बेचने के स्थान पर स्वर्ण को बैंक में गिरवी रखकर उसके विरुद्ध बैंक से आसानी से स्वर्ण ऋण प्राप्त करना ज्यादा उचित माना जाता है। और फिर, हाल ही के वर्षों में भारतीय शेयर बाजार बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है और विभिन्न कम्पनियों के शेयरों में किए गए निवेश पर 12 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की आय प्रतिवर्ष होने लगी है। इससे बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय नागरिक (खुदरा निवेशक) शेयर बाजार में निवेश करने हेतु आकर्षित हुए हैं।

दिसंबर तक एक लाख लोगों को नौकरी देगी मोहन सरकार

11 विभाग कर रहे काम...

मध्यप्रदेश सरकार दिसंबर तक एक लाख नौकरियां देने वाली है। इसके अलावा प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन आयोग की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। नवंबर में दौरे शुरू होंगे और तहसील, विकास खंड स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। दिवाली के लिए प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को 28 अक्तूबर को ही वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित हुई। इस दौरान विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी। दिवाली को देखते हुए 28 अक्तूबर तक सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन जारी कर दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दी। उन्होंने कहा कि विभागों में मैनपॉवर की कमी है। इस वजह से काम में देरी हो रही है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और राज्य प्रशासनिक सेवा के जरिए भर्ती की जाएगी। 7,900 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक केंद्रों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। 12,600 मिनी आंगनवाड़ियों में सहायिका का पद, 476 पर्यवेक्षक पद भी मंजूर किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ रुपये सालाना खर्च आएगा। केंद्र सरकार से 34 करोड़ का अनुदान राज्य सरकार को मिलेगा। रोजगार सृजन के लिए 11 विभाग काम कर रहे हैं। अगले चार साल के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कितने रोजगार के अवसर तैयार किए जा सकते हैं, इसकी रूपरेखा बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सातवां वेतनमान उन्हें दिया जाएगा। 2016 के बाद जो भी रिटायर हुए हैं, उन्हें यह लाभ मिलेगा।

रीवा में एयरपोर्ट के लिए पीएम का आभार : कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने रीवा में एयरपोर्ट के शुभारंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। विंध्य इलाके में 46 साल बाद एयरपोर्ट की सौगात मिली है। विंध्य में नेशनल पार्क, सीमेंट हब, पॉवर हब है। इसे देखते हुए कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है।

प्रशासनिक स्तर पर होगा बदलाव : मध्यप्रदेश में प्रशासनिक इकाई में बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग के सदस्यों के दौरे नवंबर में शुरू होंगे। तहसील, विकास खंड, जिला स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। बदलाव के लिए चार-पांच महीने का समय तय किया गया है। फीड बैक के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सरकार की मंजूरी मिलने पर उसे लागू किया जाएगा।

रीवा में कल इन्वेस्टर समिट : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि रीवा में बुधवार को रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है। खनिज, फूड पार्क सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। बुधवार को फार्मा सेक्टर पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। रीजनल इन्वेस्टर समिति की अच्छी तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वहां मौजूद रहेंगे। इस समिट के लिए 4,000 उद्योगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। राज्य सरकार ने उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अखाड़ों और साधु-संतों के लिए प्लॉटिंग की जाएगी। आश्रम तैयार किए जाएंगे। प्रति अखाड़ा पांच बीघा जमीन दी जाएगी। इस जमीन पर आवासीय और कमर्शियल काम नहीं हो सकेगा। सिर्फ धार्मिक उद्देश्य के लिए ही जमीन का इस्तेमाल हो सकेगा।

रेप पीड़िताओं को 4000 महीने देगी सरकार, नाबालिग प्रेग्नेंट होंगी तभी मदद...

सरकार के पास रेप से जन्मे बच्चों के परवरिश की भी स्कीम

मध्यप्रदेश सरकार प्रेग्नेंट नाबालिग रेप पीड़िताओं और रेप से जन्मे उनके बच्चों की परवरिश करेगी। जल्द सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। योजना केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव भी पास हो गया है। इस योजना का संचालन निर्भया फंड से किया जाएगा। मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चे की देखभाल के लिए पीड़िता को 23 साल की उम्र या रोजगार मिलने तक (जो भी पहले हो) 4000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा दिया जाएगा।

मोहन सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब लगातार कांग्रेस सरकार को प्रदेश में बढ़ती रेप-गैंगरेप, खासकर बच्चियों से यौन शोषण की घटनाओं पर घेर रही है।

एग्रीगेट पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट की स्थिति में पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) की धारा 6 के अंतर्गत यह सुविधा दी जाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर सेक्शुअल असॉल्ट के गंभीर हमले या रेप के कारण नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो जाती है, तो ही उसे इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। इसके लिए पीड़िता के पास एफआईआर की कॉपी होना जरूरी नहीं है।

रेप पीड़िता के बच्चे-बच्चियों को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 27 में गठित बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। यह काम कोई पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई का कोई अधिकारी, श्रम कानून में नियुक्त इंस्पेक्टर में से कोई भी कर सकेगा। इसके अलावा कोई भी राज्य शासन से मान्यता प्राप्त लोक सेवक, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा, स्वैच्छिक, गैर सरकारी संगठन, कोई एजेंसी भी ऐसे बच्चों को समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बना मॉनिटरिंग ग्रुप

मोदी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे शिवराज सिंह

म प्र के पूर्व सीएम और वर्तमान में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक और अहम जिम्मेदारी दी है। पीएम ने कृषि मंत्री को केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम के लिए बनाए गए मॉनिटरिंग ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह निगरानी समूह मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का क्रियान्वयन करेगा और उनकी स्टेटस रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजेगा। दिल्ली में निगरानी समूह की पहली बैठक 18 अक्टूबर को हुई है। इस मीटिंग में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों ने भाग लिया था। अब हर महीने इस मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग होगी।

शिवराज सिंह चौहान से पहले यह जिम्मेदारी केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया संभाल रहे थे। मांडविया से पहले इस निगरानी समूह के अध्यक्ष केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल थे। इस निगरानी समूह के अध्यक्ष की जिम्मेदारी अहम मानी जाती है। क्योंकि, वर्तमान योजनाओं में कौन सा बदलाव करना है या कौन सी नई स्कीम शुरू करनी है इस पर यही ग्रुप फैसला लेकर मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजता है। नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए निगरानी समूह का गठन किया था। फिर 2019 में सरकार के गठन के बाद इसका पुनर्गठन किया गया था। अब तीसरी बार इसका गठन किया गया है। इस ग्रुप का उद्देश्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं की समीक्षा करना और उनकी खामियों के

बारे में बताना है। यह ग्रुप केन्द्रीय बजट, अधीनस्थ विधान तथा अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास पर हुई मीटिंग में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सहित भारत सरकार के सभी सचिव शामिल हुए थे।

2014 से लेकर अब तक के कामकाज की होगी समीक्षा : शिवराज सिंह चौहान की अगुआई में यह टीम साल 2014 यानी पहली एनडीए सरकार के कार्यकाल से लेकर अब तक घोषित परियोजनाओं की समीक्षा करेगी। अगर किसी परियोजना में कोई देरी, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यह टीम संबंधित प्रोजेक्ट्स के सचिवों से संपर्क करेंगे।

शिक्षा विभाग के अधिकारी को 4 साल की कैद

5 हजार रुपए की रिश्वत पर 8 साल बाद फैसला, निजी स्कूल प्राचार्य से की थी मांग

रिश्वतखोरी के मामले में कोर्ट ने एक अधिकारी को 4 साल की सजा सुनाई है। आरटीई के तहत निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के प्रमाणीकरण के संबंध में रिश्वत मांगी गई थी। मामले में 8 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। दरअसल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय में विशेष न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की कोर्ट ने 18 अक्टूबर को तत्कालीन नोडल अधिकारी गजेंद्र देशमुख को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार दिया है और 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी एरोड्रम रोड स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी नगर में उच्च श्रेणी शिक्षक होने के साथ नोडल अधिकारी भी था। आरोपी नोडल अधिकारी होने के नाते उसके पास निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ने वाले बच्चों का निरीक्षण कर इसका प्रमाणीकरण करने का अधिकार भी था। उसने गांधी नगर स्थित ब्लासम एकेडमी स्कूल का नवंबर 2016 में निरीक्षण किया था। उसे प्रमाणीकरण फार्म पर हस्ताक्षर करना था लेकिन वह प्राचार्य विनीता वर्मा से रिश्वत की मांग करते हुए लगातार

टाल रहा था, जिस पर प्राचार्य ने देशमुख से बातचीत के ऑडियो की 3 मेमोरी कार्ड के साथ लोकायुक्त को इस मामले में शिकायत की थी।

लोकायुक्त में शिकायत के बाद योजना अनुसार दोपहर में फरियादी प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी नगर पहुंचीं तब आरोपी गजेंद्र स्कूल में नोडल अधिकारी कक्ष में बैठा था। फरियादी ने उसे 5 हजार रुपए दिए जो उसने अलमारी में रखे ही थे कि वहां तैनात लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस के निरीक्षक महेश सुनैया और निरीक्षक आशा शेजकर ने आरोपी से 5 हजार रुपए जब्त कर उसे भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। जिस पर 8 साल बाद कोर्ट ने गजेंद्र देशमुख को 4 साल की सश्रम सजा और 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया है।

सीएम बोले- हरिद्वार के तर्ज पर करेंगे विकसित

उज्जैन में साधु-संतों के लिए बनाए जाएंगे स्थायी आश्रम

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में हरिद्वार के तर्ज पर साधु संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर इत्यादि को स्थाई आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी। उज्जैन की पहचान साधु संतों से है। 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला सिहंस्थ का आयोजन 2028 में किया जाएगा।

साधु संतों को उज्जैन में आने, ठहरने, कथा, भागवत इत्यादि अन्य आयोजन के लिए पर्याप्त रूप से भूमि भू-खंड की आवश्यकता पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा साधु -संतों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्थायी आश्रम बनाए जाने की योजना बनाई गई हैं। निजी होटल्स में साधु संतों और श्रद्धालुओं को इस प्रकार के आयोजनों के लिए चुनौतियां आती हैं। महंगा भी पड़ता है। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज उज्जैन के मेला कार्यालय, उज्जैन के ऑडिटोरियम में सिंहस्थ के संबंध में आयोजित प्रेस-वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया,राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय,महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, संभागायुक्त संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

हरिद्वार के तर्ज पर बनेंगे आश्रम : मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि हरिद्वार में जिस प्रकार साधु -संतों के अच्छे आश्रम बने हुए हैं,उसी प्रकार विकास के क्रम को जारी रखते हुए उज्जैन में भी साधु संतों के स्थायी आश्रम बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से

इस बड़ी योजना को आकार दिया जाएगा। सभी साधू-संतो, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर सभी को आमंत्रित कर उनके स्थायी आश्रम बनाने की दिशा में काम करेंगे।

सिंहस्थ के दृष्टिगत सड़क, बिजली, पेयजल, जल निकासी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी स्थाई अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। ताकि अस्थाई निर्माण से होने वाली समस्याएं निर्मित ना हो। हरिद्वार की तरह उज्जैन को धार्मिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार की गई है।

अधोसंरचना विकास : सभी प्रकार के फोरलेन, सिक्सलेन ब्रिज आदि स्थायी अधोसंरचना विकास के कार्य किए जाएंगे। सभी मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ साधु -संतों के लिए आश्रम निर्माण के कार्य समानांतर रूप से किए जाएंगे। समाज के इच्छुक सनातन धर्मावलंबियों के माध्यम से अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, आश्रम, चिकित्सा केंद्र, आयुर्वेद केंद्र आदि सार्वजनिक गतिविधियों के संचालन कार्य को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि उज्जैन सहित प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। समान रूप से विकास से सभी की खुशहाली के द्वार खुलेंगे। सभी देव स्थानों के आसपास हमारे धर्माचार्य आ जाए यह हमारी प्राथमिकता हैं।

5 बीघा में आश्रम और पार्किंग

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि साधु -संतों को आश्रम निर्माण के लिए अनुमति इस प्रकार दी जाएगी कि 5 बीघा के एक भूखंड पर ही भवन का निर्माण किया जा सकेगा। शेष 4 बीघा भूखंड खुला रहेगा, जिसमें पार्किंग आदि व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त खुला स्थान रहे। यह अनुमति केवल साधु-संतों ,महंत ,अखाड़ा प्रमुखों,महामंडलेश्वर को ही दी जाएगी। व्यक्तिगत और कमर्शियल उपयोग के लिए इस प्रकार की अनुमति नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि महाकाल महालोक बनने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। निरंतर यहां धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी रहता है। ऐसे में यह योजना धर्मावलंबियों के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि उज्जैन -इंदौर सिक्स लेन कार्य की भी टेंडर प्रक्रिया हो गई है। वहीं उज्जैन- जावरा ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग का शीघ्र भूमिपूजन किया जाएगा। इसी प्रकार बृहद योजना के तहत इंदौर उज्जैन धार,भोपाल , ग्वालियर , जबलपुर आदि को विकसित किया जाएगा। उज्जैन के धार्मिक मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे।

क्या संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटेगा? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा?

क्या संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाये जायेंगे? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाये। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने जो छेड़छाड़ की थी उसे ठीक किया जाये। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसकी प्रस्तावना से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ गैरकानूनी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। उन्होंने कहा है कि जब देश में आपातकाल लगा था और विपक्ष के सारे नेता जेल में थे तब बिना किसी चर्चा के राजनीतिक कारणों से संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द डाले गये थे जोकि असंवैधानिक है।

हम आपको बता दें कि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यह कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान की मूल भावना के मुताबिक ही हैं हालांकि बाद में अदालत ने कहा कि वह 18 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह के दौरान इस संबंध में विस्तार से याचिकाकर्ताओं की बात सुनेगा। हम आपको बता दें कि

सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में तीन याचिकाएं दाखिल गयी हैं। इनमें अश्विनी उपाध्याय के अतिरिक्त बलराम सिंह और सुब्रमण्यम स्वामी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अश्विनी उपाध्याय ने खुद तर्क प्रस्तुत किये तो वहीं बलराम सिंह की ओर से उनके वकील विष्णु जैन ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी। अश्विनी उपाध्याय ने जब यह कहा कि संविधान सभा ने चर्चा के बाद यह तय किया था कि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं होगा तो इस पर दो जजों वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल उठाया कि क्या आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष रहे? इस दौरान तीसरे याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को विस्तार से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देखना चाहिए कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था, लेकिन 1976 में उसे बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के बाद भी संविधान की प्रस्तावना में यही लिखा है कि उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इस बात पर जजों ने सहमति जताई कि पुरानी तारीख को बरकरार रखते हुए इस तरह नई बातें जोड़ दिए जाने के मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है।

उच्च शिक्षित महिला का भत्ता हाईकोर्ट ने कम किया, कहा

किसी के भरोसे क्यों बैठा जाए जब खुद कमाने में सक्षम हो

हाइ कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का प्रावधान कानून निर्माताओं द्वारा निष्क्रिय लोगों की सेना बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। कोई उच्च शिक्षित है, खुद कमाने में सक्षम है तो क्यों किसी पर निर्भर रहा जाए। हाई कोर्ट ने पत्नी को पति द्वारा दिया जाने वाला भरण-पोषण भत्ता कम करने के आदेश दिए। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने याचिकाकर्ता की पोस्ट ग्रेजुएट पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ते को कम करते हुए कहा कि कहीं भी प्रकट नहीं हुआ है कि सक्षम और सुयोग्य महिला को अपने भरण-पोषण के लिए हमेशा अपने जीवन साथी पर निर्भर रहना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसकी पत्नी एमकॉम होने के कारण अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। महिला ने पीजी की डिग्री हासिल करने के साथ-साथ

उसने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है और वर्तमान में एक डांस क्लास चलाती है। न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि शैक्षणिक योग्यता रखने से पत्नी को लाभ प्राप्त नहीं होने की स्थिति में गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, पत्नी ने अतीत में काम किया था और अपनी योग्यता और क्षमताओं को देखते हुए आय अर्जित कर सकती थी।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख किया- हमने महिला को दिए जा रहे 25,000 रुपए प्रति माह के प्रारंभिक रखरखाव भत्ते को उच्च स्तर पर पाया और कुछ आय अर्जित करने की महिला की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे घटाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। वहीं, महिला के साथ रह रही बेटी के वयस्क होने तक उसके लिए दिए जाने वाले 15,000 रुपए प्रति माह के भत्ते को भी बरकरार रखा है। याचिकाकर्ता पति ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19(4) के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। उसमें दावा किया गया था कि फैमिली कोर्ट के भरण-पोषण के आदेश के कारण उसे काफी वित्तीय कठिनाई हुई है, क्योंकि वह अपने पिता और भाई का भरण-पोषण कर रहा है।

चौंकाने वाले हैं जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम

सियासी मायने

पहली बार चुनाव हुए। जिसमें बीजेपी का जलवा कायम रहा, जबकि वह सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। अतीत पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार वर्ष 2014 में चुनाव हुए थे। वहां पर साल 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम एक बार फिर सबको चौंका दिए। यहां भाजपा की कसरत बेकार गई और कांग्रेस की फितरत नेशनल कांफ्रेंस के सहारे बाजी मार ले गई। कहने का तातपर्य यह कि ताजा चुनाव परिणाम से जहां एक ओर पाकिस्तान-चीन परस्त स्थानीय सियासत को हवा देने वाली कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस के देशद्रोही एजेंडे को सुकून मिली है, वहीं सूबे में भारतीयता की अलख जगाने वाली भाजपा की राष्ट्रवादी सियासत के ऊपर चिंता की कुछ नई लकीरें खींच दी हैं, जिन्हें समय रहते ही मिटाने के कुछ और सकारात्मक प्रयत्न करने होंगे।

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इस चुनाव परिणाम से वहां सक्रिय हिन्दू हित चिंतक समूहों की भी बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि एक बार फिर वहां पर वही 'अब्दुल्ला' सरकार लौट रही है, जिसे जम्मू-कश्मीर के लिए हर मायने में अलग स्टेटस चाहिए। यानी धारा 370 की वापसी चाहिए। चूंकि काँग्रेस भी उसकी हां में हां मिला रही है, इसलिए केंद्र में सरकार बदलते ही उनकी जिद्द पूरी हो सकती है, हालांकि उनके लिए दिल्ली अभी दूर है।

देखा जाए तो अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए। जिसमें बीजेपी का जलवा कायम रहा, जबकि वह सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। अतीत पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार वर्ष 2014 में चुनाव हुए थे। वहां पर साल 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद वहां बीजेपी और पीडीपी गठबंधन ने सरकार चलाई।

इसी बीच 2019 में वहां से अनुच्छेद 370 को हटाया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब से वहां उपराज्यपाल शासन लागू है। उसके बाद अब जाकर साल 2024 में यहां चुनाव हुए, जिसमें तीन पीढ़ियों से यहां की सत्ता चला रहे अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। घाटी में उनकी तूती

बोलती है, इसलिए वहां उन्हें काफी सीटें मिलीं। हां, जम्मू के हिंदुओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिया और अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं का खुलकर इजहार किया।

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि आतंक के साए के बीच 10 साल बाद फिर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। इससे पहले 2014 से 2024 के बीच 10 साल में जम्मू-कश्मीर का पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर घाटी की राजनीतिक हवा ही पूरी तरह से बदल गई। केंद्र शासित प्रदेश के नए स्वरूप में आने वाले इस राज्य में आखिरकार 2024 में फिर से विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा। और जब जम्मू व कश्मीर के चुनाव परिणाम आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीतीं। जबकि, बीजेपी ने 29 सीटों पर कब्जा किया। वहीं, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिलीं। जबकि अन्य छोटी पार्टियों ने 10 सीटें हासिल कीं। यदि अलग अलग सीटों की बात की जाए तो नैशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। जबकि जेपीसी को 1, सीपीआई एम को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और निर्दलीय को 7 सीटें मिली हैं। जहां तक इनके वोट प्रतिशत का सवाल है तो बीजेपी को 25.64 प्रतिशत, नैशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43 प्रतिशत, कांग्रेस को 11.97 प्रतिशत, पीडीपी को 8.87, आम आदमी पार्टी को 0.52 प्रतिशत, बीएसपी को 0.96 प्रतिशत और जदयू को 0.13 प्रतिशत वोट मिले हैं। इस चुनाव में कुल 63.45 फीसदी वोटिंग हुई है। बता दें कि विधानसभा की 90 सीटों के लिए तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान हुए थे। ताजा चुनाव परिणाम से स्पष्ट होता है कि कभी भाजपा की करीबी रहीं पीडीपी नेत्री व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को मतदाताओं ने खारिज कर दिया, ताकि वह भाजपा के साथ गठबंधन करने लायक ही नहीं बचें। उल्लेखनीय है कि साल 2014 में महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी ने मिलकर पहली बार गठबंधन किया और जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाई। यह वो नाजुक वक्त था जब 10 साल बाद बीजेपी ने फिर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता पर आसीन हुई थी।

उसी समय लीक से हटकर बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन किया और चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाई। हालांकि ये बेमेल सरकार रही। वहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ़्ती सीएम बनीं। चूंकि पीडीपी का एजेंडा बीजेपी के एजेंडे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था और घाटी में पत्थरबाजी आम हो चली थी। इसलिए बीजेपी ने पीडीपी प्रमुख महबूबा से अपना पीछा छुड़ाना ही उचित समझा और ताबड़तोड़ उचित फैसले लिए।

साल 2014 से ही घाटी की राजनीति और जम्हूरियत का हवाला देने वाले फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला अपनी विचारधारा पर दृढ़ता से खड़े रहे। देखा गया कि भले ही वो अटलजी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, एनडीए में भी शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद वे नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों पर लगातार मुखरित रहे। पूरे देश में राहुल गांधी और जम्मू-कश्मीर में फारुख अब्दुल्ला-उमर अब्दुल्ला अपनी मुखरता के लिए ही जाने-पहचाने गए। वहीं, जब 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 (ए) हटाया गया, तो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने ही इस पर मुखरता पूर्वक अपनी बात रखी। इससे पाक व चीन परस्त जम्मू-कश्मीर वासियों के हौसले बढ़े। बता दें कि साल 2014 में जम्मू-कश्मीर चुनाव से पहले अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही राज था। तब उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 5 जनवरी 2009 को गठबंधन सरकार बनाई थी।

वहीं, जब अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म किया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये सब कुछ करने के बाद यह पूरा क्षेत्र उबल पड़ा, जिसके दृष्टिगत जम्मू-कश्मीर में कई महीनों तक विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लागू रहे। इन सबके बाद भी जब जम्मू कश्मीर में साल 2024 में विधानसभा चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला परिवार के पुनर्वापसी हुई, जबकि पीडीपी के महबूबा परिवार का सियासी सुफड़ा साफ हो गया।

सवाल है कि जब भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी अब्दुल्ला परिवार की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस की लाइन पर ही चल रही थी, तो फिर उनकी पीडीपी को विधानसभा की 90 सीटों में से महज 3 सीटें ही क्यों मिल पाईं। शायद इसलिए कि जब कश्मीर घाटी में युवाओं ने पत्थरबाजी कर आतंक मचा रखा था, तब महबूबा की भाषा ऐसी थी कि किसी को भी हैरान कर दे। तब जिस तरह से उनकी वक्तव्यों में पाकिस्तान के प्रति झुकाव स्पष्ट देखने को मिलता था, उससे भारत में आस्था रखने वाले कश्मीरी क्षुब्ध दिखते थे। यही वजह है कि जब चुनाव आए तो मतदाताओं ने उन्हें सिरे से ही खारिज कर दिया, जो उनके लिए भी सियासी अजूबे की तरह है।

आपको पता होना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पिता और यहीं के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मित्र समझे जाते थे, ने घाटी की सियासत में अहम भूमिका अदा की। सच कहूं तो शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति के 'पायोनियर' थे। वे ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। वो जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के बाद वहां के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।

यही वजह है कि पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को अपने पिता से राजनीति विरासत में मिली। उन्होंने भी भाजपा से गठबंधन किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसप्रकार दशकों तक कश्मीर घाटी की मुखर आवाज रहने के बाद उन्होंने अपनी विरासत अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को सौंप दी। बता दें कि साल 2009 से साल 2014 तक उमर अब्दुल्ला जम्मू- कश्मीर के सीएम रहे। दस साल बाद फिर उनकी सियासी किस्मत चमकी और वो यहां के अगले सीएम बनेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के गठबंधन को ही पूर्ण बहुमत मिला है।

आपको पता होना चाहिए कि देश पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली कांग्रेस की कभी जम्मू-कश्मीर में तूती बोलती थी। तब घाटी में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने भी जम्मू-कश्मीर में अपनी सरकार चलाई। हालांकि ग्रुप 23 के झांसे में आकर कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने के बाद गुलाम नबी आजाद व उनके समर्थकों का भी राजनीतिक वजूद खत्म हो गया। इसी तरह कांग्रेस का भी स्वतंत्र पार्टी के रूप में वजूद खत्म हो गया।

इस बार जम्मूकश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलाम नबी आजाद की घरवापसी के लिए पहल की, लेकिन राहुल गांधी के सख्त रवैये के चलते खड़गे बैक फुट पर चले गए। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी पार्टी बनकर कांग्रेस 6 सीटें पाने में सफल रही। इस मामूली उपलब्धि के लिए भी राहुल गांधी ने जम्मू और कश्मीर में कई रैलियां की। उधर, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपनी ताकतवर मौजूदगी दिखाई थी। इसका असर यह रहा कि कांग्रेस को महज 6 सीटें मिल गईं।

हिंदु बहुल जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले अच्छा रहा। पार्टी ने यहां 29 सीटें जीतीं। बता दें कि जम्मू रीजन में 43 सीटें पड़ती हैं। भाजपा 68 प्रतिशत की स्ट्राइक रेट के साथ ये सीटें हासिल की है, जो बड़ी बात है।

इस तरह बीजेपी पूरे जम्मू-कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं, कश्मीर घाटी में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी सभी 25 सीटें जम्मू में ही जीती थीं। तब भी कश्मीर में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी।

हालांकि इस बड़ी जीत के लिए यहां पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों की रैलियां हुईं। इसके बावजूद भी जम्मू के बाहर भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। समझा जाता है कि जम्मू के हिंदुओं ने आतंक का दंश झेला है। अनुच्छेद 370 हटने पर पीडीपी और नेकां के बयानों को भी सुना है। इसलिए जब चुनाव आए तो हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट डाले। इससे बीजेपी का सियासी ग्राफ भी ऊंचा उठा। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को अकेले जम्मू में ही कम से कम 30 से 35 सीटें जीतना जरूरी था। जबकि, घाटी में भी उसे अच्छा प्रदर्शन करना था। हालांकि, ऐसा हो नहीं सका।

समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव 'ग्लोबल साउथ' के देशों पर पड़ने का उल्लेख करते हुए यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता की बहाली का आह्वान किया

मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) को संबोधित करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत पूरे क्षेत्र में शांति तथा प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हित में है।

मोदी ने कहा, "हमारा मानना है कि समुद्री गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के तहत संचालित की जानी चाहिए। नौवहन और वायु क्षेत्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। एक मजबूत और प्रभावी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। और इससे क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर कोई अंकुश नहीं लगना चाहिए।" उन्होंने कहा, "हमारा दृष्टिकोण विकासवाद का होना चाहिए, न कि विस्तारवाद का।

विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे संघर्षों का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव 'ग्लोबल साउथ' के देशों पर पड़ने का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि चाहे वह यूरेशिया हो या पश्चिम एशिया, हर कोई चाहता है कि यथाशीघ्र शांति और स्थिरता बहाल होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं बुद्ध की धरती से आता हूं और मैंने बार-बार कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना आवश्यक है। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देनी होगी।" उन्होंने कहा कि विश्वबंधु की जिम्मेदारी निभाते हुए भारत इस दिशा में हरसंभव योगदान देता रहेगा। उनकी यह टिप्पणी यूरेशिया में यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष तथा पश्चिम एशिया में इजराइल- हमास युद्ध के बीच आई है।

मोदी ने कहा, "आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। इसका सामना करने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाली ताकतों को मिलकर काम करना होगा।" अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने "तूफान यागी" से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। यागी एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने इस वर्ष सितंबर में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन को प्रभावित किया था। मोदी ने कहा, "इस कठिन समय में हमने ऑपरेशन सद्भाव के जरिये मानवीय सहायता प्रदान की है।"

उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) की एकता और प्रमुखता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आसियान भारत के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण और क्वाड सहयोग के केन्द्र में भी है। उन्होंने कहा, "भारत की 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' और 'हिंद-प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण' के बीच गहरी समानताएं हैं।"

मोदी ने कहा, "हम म्यांमा की स्थिति के प्रति आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। हम पांच सूत्री सहमति का भी समर्थन करते हैं। साथ ही, हमारा मानना है कि वहां मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि इसके लिए म्यांमा को शामिल किया जाना चाहिए, अलग-थलग नहीं किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के रूप में भारत अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। मोदी ने कहा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

दवा कारोबार की अनैतिकता से बढ़ता जीवन संकट

आम लोगों के मन में सवाल बाकी है कि यदि ये दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरती तो इनके नकारात्मक प्रभाव किस हद तक हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं। यह भी कि जो लोग घटिया दवाइयां बेच रहे थे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की पहल भी हुई है?

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने दवाइयों के क्वालिटी टेस्ट में 53 दवाओं को फेल कर दिया गया है। उनमें कई दवाओं की क्वालिटी खराब है तो वहीं दूसरी ओर बहुत सी दवाएं नकली भी बिक रही हैं। इन दवाओं में बीपी, डायबिटीज, एसिड रिफलक्स और विटामिन की कुछ दवाइयां भी शामिल हैं। इसके अलावा सीडीएससीओ ने जिन दवाओं को गुणवत्ता में फेल किया हैं उसमें बुखार उतारने वाली पैरासिटामोल, पेन किलर डिक्लोफेनेक, एंटीफंगल मेडिसिन फ्लुकोनाजोल जैसी देश की कई बड़ी फार्मास्युटिक्लस कंपनी की दवाएं भी शामिल हैं और इनको सेहत के लिए नुकसानदायक भी बताया गया है। निश्चित ही यह खबर परेशानी एवं चिन्ता में डालने वाली है। कैसी विडंबना है कि काफी समय से सरकारों की नाक के नीचे ये दवाइयां धड़ल्ले से बिकती रही हैं। गुणवत्ता के मानकों पर खरा न उतरने वाली दवाओं की सूची जारी होने से उन मरीजों की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गयी हैं जो इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। दुर्भाग्य से इस सूची में हाइपरटेंशन, डाइबिटीज, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन-डी3 सप्लीमेंट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन-सी, एंटी-एसिड, एंटी फंगल, सांस की बीमारी रोकने वाली दवाएं भी शामिल हैं। इसमें दौरे व एंग्जाइटी का उपचार करने वाली दवाएं भी शामिल हैं। ये दवाएं बड़ी कंपनियों द्वारा भी उत्पादित हैं। विटामिन और फ़ूड सप्लीमेंट खरीदें

रोगी इस उम्मीद में दवा लेते हैं कि इससे उनकी बीमारी ठीक होगी। लेकिन यह पता लगे कि जिन दवाइयों का वे सेवन कर रहे हैं वे दवा नहीं बल्कि जहर के रूप में बाजार में आ गई हैं तो क्या बीतेगी? हिंदुस्तान में आज लाखों लोगों को ये दवाएं जीवन-रक्षा नहीं दे रही है बल्कि मार रही है, इंसान का लोभ एवं लालच इंसान को मार रहा है। ऐसे स्वार्थी लोगों एवं जीवन से खिलवाड़ करने वालों को राक्षस, असुर या दैत्य कहा गया है जो समाज एवं राष्ट्र में तरह-तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर मौत बांट रहे हैं। अमानक एवं गुणवत्ता में दोषपूर्ण पाई गई इन दवाओं में कई नामी कंपनियों की दवाएं भी शामिल हैं। अमानक पाई गई दवाइयों के ये मामले तो तब आए हैं जब पहले से ही दवाओं की गुणवत्ता तय करने के लिए कई सख्त प्रक्रियाएं होती हैं। इनमें कच्चे माल की जांच और निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण तक शामिल होता है। इसके बावजूद नामी दवा निर्माता कंपनियों के उत्पाद भी मानकों पर खरे नहीं उतरें तो यह माना जाना चाहिए कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये कंपनियां नैतिकता एवं मानवीयता को ताक पर रखने लगी है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब दवाइयां गुणवत्ता

के पैमानों पर खरी नहीं उतरी हैं।

आम लोगों के मन में सवाल बाकी है कि यदि ये दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरती तो इनके नकारात्मक प्रभाव किस हद तक हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं। यह भी कि जो लोग घटिया दवाइयां बेच रहे थे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की पहल भी हुई है? फिलहाल इस बाबत कोई जानकारी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। निस्संदेह, यह शर्मनाक है और तंत्र की विफलता को उजागर करता है कि शारीरिक कष्टों से मुक्त होने के लिये लोग जो दवाएं खरीदते हैं, वे घटिया हैं? बहुत संभव है ऐसी घटिया दवाओं के नकारात्मक प्रभाव भी सामने आते होंगे। इस बाबत गंभीर शोध-अनुसंधान की जरूरत है। चिंता यह भी कि यदि रैंडम सैम्पलिंग में ये दवाइयां पकड़ी नहीं जाएं तो इनकी खुलेआम बिक्री लोगों की सेहत पर खतरा बन कर मंडराती रहती हैं। एक तरफ सीडीएससीओ ने दवाओं की सुगम आपूर्ति के लिए अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा व यूरोपीय संघ के कुछ चुनिंदा देशों से आयातित दवाओं को नियमित नमूना परीक्षण से छूट दी है, वहीं देश के बाजारों में पहुंची दवा निर्माता कंपनियों की दवाओं में मिलने वाली यह खोट हमारी छवि पर विपरीत असर डालने वाली है।

दवा परीक्षण में किसी भी स्तर पर लापरवाही अक्षम्य ही है क्योंकि दवा कारोबार में हेराफेरी का खेल लोगों की जान का दुश्मन बन सकता है। विडंबना देखिए कि ताकतवर और धनाढ्य वर्ग द्वारा संचालित इन दवा कंपनियों पर राज्य सरकारें भी जल्दी हाथ डालने से कतराती हैं। जिसकी कीमत आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानवीय मूल्यों में इस हद तक गिरावट आई है कि लोग अपने मुनाफे के लिये पीड़ित मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूक रहे हैं। व्यथित करने वाली बात है कि गुणवत्ता एवं मानक में फेल होने वाली दवाओं में पेट में इंफेक्शन रोकने वाली एक चर्चित दवा भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि इसी साल अगस्त में केंद्र सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल, ये दवाइयां आमतौर पर सर्दी व बुखार, दर्द निवारक, मल्टी विटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। मरीजों के लिये नुकसानदायक होने की आशंका में इन दवाइयों के उत्पादन, वितरण व उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। सरकार ने यह फैसला दवा टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर लिया था। जिसका मानना था कि इन दवाओं में शामिल अवयवों की चिकित्सकीय गुणवत्ता संदिग्ध है। दरअसल, एक ही गोली को कई दवाओं से मिलाकर बनाने को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स यानी एफडीसी कहा जाता है। बहरहाल, सामान्य रोगों में उपयोग की जाने वाली तथा जीवनरक्षक दवाओं की गुणवत्ता में कमी का पाया जाना, मरीजों के जीवन से खिलवाड़ ही है। जिसके लिये नियामक विभागों की जवाबदेही तय करके घटिया दवा बेचने वाले दोषियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। असल में इस तरह की दानवी सोच वाले लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं।

भाजपा के हिन्दुत्व में रुकावट है एससी-एसटी पर अत्याचार...

इस रिपोर्ट में जांच और चार्जशीट से संबंधित डेटा भी प्रस्तुत किया गया है। अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों में 60.38 प्रतिशत मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, जबकि झूठे दावों या सबूतों की कमी के कारण 14.78 प्रतिशत मामलों में अंतिम रिपोर्ट दी गई।

हिन्दुओं की एकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का यह सपना शायद ही कभी पूरा हो सकेगा। देश में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचारों के मामले में देशभर में उत्तरप्रदेश पहले, मध्यप्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। सर्वाधिक आश्चर्य यह है कि हाशिए पर रह रहे इन वर्गों पर अत्याचारों का मामला राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन सका। इन वर्गों की दुहाई के लिए घडियाली आंसू बहाने वाले राजनीतिक दलों और संगठनों ने इन अत्याचारों पर धरना-प्रदर्शन करना तो दूर मुंह तक नहीं खोला। भाजपाशासित राज्यों में एससी-एसटी पर अत्याचार शीर्ष पर होने के बावजूद यह मुद्दा चिंता का विषय नहीं बन सका। अत्याचारों के आंकड़ों की यह तस्वीर भाजपा के हिन्दुओं के एकता की सच्चाई उजागर करती है।

एक सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों (एसटी) के खिलाफ 97.7 प्रतिशत अत्याचार 13 राज्यों में केंद्रित थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले (23.78 प्रतिशत), राजस्थान में 8,651 मामले (16.75 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले (14.97 प्रतिशत) दर्ज किए गए। इसके अलावा अन्य राज्यों में अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें बिहार में 6,799 मामले (13.16 प्रतिशत), ओडिशा में 3,576 मामले (6.93 प्रतिशत) और महाराष्ट्र में 2,706 मामले (5.24 प्रतिशत) शामिल हैं। वर्ष 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए कुल मामलों में से लगभग 81 प्रतिशत केवल इन छह राज्यों में दर्ज किए गए।

इस अधिनियम के तहत 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ कुल 51,656 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ये मामले भारतीय दंड संहिता के तहत भी दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि एसटी के खिलाफ अत्याचार के अधिकांश मामले भी 13 राज्यों में हुए। एसटी से जुड़े 9,735 मामलों में से मध्य प्रदेश में 2,979 मामले (30.61 प्रतिशत), राजस्थान में 2,498 मामले (25.66 प्रतिशत) और ओडिशा में 773 मामले (7.94 प्रतिशत) दर्ज किए गए। एसटी से संबंधित अन्य मामलों में महाराष्ट्र में 691 मामले (7.10 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश में 499 मामले (5.13 प्रतिशत) शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में जांच और चार्जशीट से संबंधित डेटा भी प्रस्तुत किया गया है। अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों में 60.38 प्रतिशत मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, जबकि झूठे दावों या सबूतों की कमी के कारण 14.78 प्रतिशत मामलों में अंतिम रिपोर्ट दी गई। वर्ष 2022 के अंत तक 17,166 मामलों की जांच अभी भी लंबित थी। अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में 63.32 प्रतिशत मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, जबकि 14.71 प्रतिशत मामलों में अंतिम रिपोर्ट दी गई। 2022 के अंत तक 2,702 मामलों की जांच जारी थी। रिपोर्ट में एक प्रमुख चिंता अधिनियम के तहत दोषसिद्धि दर में गिरावट है; साल 2022 में यह दर 2020 के 39.2 प्रतिशत से घटकर 32.4 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट में इन मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों की अपर्याप्त संख्या पर भी चिंता व्यक्त की गई है। 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 जिलों ने विशेष अदालतें स्थापित की हैं ताकि मामलों की तेजी से सुनवाई हो सके। रिपोर्ट में ऐसे विशिष्ट जिलों की पहचान की गई है जहां अत्याचार की घटनाएं काफी अधिक हैं, लेकिन केवल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसे जिलों की घोषणा की है।

उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में, जहां अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों की अधिक संख्या दर्ज की गई, वहां कोई अत्याचार-ग्रस्त जिला नहीं बताया गया। रिपोर्ट में जाति आधारित हिंसा को रोकने और कमजोर समुदायों के लिए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन जिलों में हस्तक्षेप करने का आह्वान किया गया है। अनुसूचित जाति-जनजाति पर अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए किए गए सरकारी उपाय दिखावटी साबित हुए हैं। यह समस्या सुरसा की तरह मुंह फाड़े चली आ रही है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में एससी/एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किये गए हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में एससी/एसटी अपराधों से निपटने के लिये विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किये गए हैं।

हरिपुरा सब्जी मंडी डबरा में मां काली की भव्य झांकी सजाई गई।

इंदौर में शराब दुकानों से मंत्री विजयवर्गीय नाराज

बड़ा गणपति से पितृपर्वत तक सड़क किनारे की शराब दुकानें होंगी बंद

अपनी ही सरकार में खोली गई शराब की दुकानों से प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नाराज दिख रहे हैं। भाजपा नेता विजयवर्गीय अपने विधानसभा क्षेत्र इंदौर-एक में शनिवार को विकास कार्यों का भूमिपूजन कर रहे थे। उनके साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी थे।

न हों शराब की दुकानें- विकास कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त में पहली कुदाली चलाते हुए मंत्री ने महापौर को निर्देश दिए कि स्वच्छता के साथ पवित्रता भी जरूरी है। अगली बार शराब के ठेके हों तो यह ध्यान रखें कि बड़ा गणपति से पितृपर्वत तक मुख्य सड़क पर शराब की दुकानें न हों। साथ ही मंत्री ने यह भी कह दिया कि इस रास्ते से मांस-मछली की दुकानें भी हटाई जाए।

शनिवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक के वार्ड पांच में मंत्री और महापौर ने करीब साढ़े चार करोड़ की लागत से होने वाली सड़क निर्माण, ड्रेनेज लाइन डाले जाने जैसे कामों के लिए भूमिपूजन किया। इसके साथ में एक क्लीनिक का लोकार्पण भी किया। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। उन्होंने कहा कि मैं नशे के खिलाफ रहता हूं। नशा करना अच्छी बात नहीं है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों मंत्री अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में दौरा कर रहे थे तब भागीरथपुरा में एक महिला ने उन्हें रोककर खुलेआम नशा बिकने की शिकायत की थी। इसके बाद मंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए थे और पुलिस नशा बेचने वालों की धर-पकड़ करती नजर भी आई थी। दुकानदारों की नाराजगी की चिंता नहीं- मंत्री विजयवर्गीय ने मंच

से महापौर से यह भी कहा कि एरोड्रम रोड शहर के चौड़े मार्गों में से एक है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि व्यापारी फुटपाथ तक सामान टांग कर कब्जा कर रखते हैं। उसके आगे काउंटर लगाते हैं और फिर सड़क के बड़े हिस्से को ग्राहकों के वाहन घेर लेते हैं। नगर निगम सड़क के दोनों तरफ एक सफेद लाइन खींचे। यदि उससे बाहर दुकान का सामान दिखे तो जब्त कर लें। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे पता है कि इससे दुकानदार नाराज हो जाएंगे, लेकिन उनकी नाराजगी की चिंता नहीं है। शहर का ट्रैफिक सुधारना भी जरूरी है।

योगी ने कहा है बंटोगे तो कटोगे, हरियाणा की जनता ने बता दिया नहीं बंटेंगे - विजयवर्गीय

विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि आने वाले 25 साल हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरे वाले है। इस बात पर गंभीरता से विचार करे,क्योकि कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश में अंशाति फैलाने वाले लोगों को सरंक्षण दे रहे है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक गरबा आयोजन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सही कहा है कि बंटोगे तो कटोगे, लेकिन हरियाणा की जनता ने बता दिया कि वे नहीं बंटेंगे।

विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि आने वाले 25 साल हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरे वाले है। इस बात पर गंभीरता से विचार करे,क्योकि जिस तरह देश की

डेमोग्राफी बदल रही है।जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश में अंशाति फैलाने वाले लोगों को सरंक्षण दे रहे है, इसलिए बहुत जरुरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चले।

नागपुर से लौटने के बाद गुरुवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कई गरबा आयोजनों में शिरक्त की। उन्होंने यहां भजन गाए। उनके भजन पर युवक-युवतियों ने गरबा भी किया। भजन गाने के दौरान ही विजयवर्गीय ने यह बयान दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा धर्म विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। हमारी परंपरा, संस्कृति सदियों पुरानी है। उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उसे कमजोर करने की कोशिश होती है। भारत ही विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकता है। कट्टरवाद कई देशों में युद्ध के जरिए अशांति और अराजकता फैला रहा है। विजयवर्गीय ने पांडाल में देवी दुर्गा की आरती भी की।

पूर्वांचल और अवध के कई जिलों में परंपरागत फसलों का विकल्प केला

कम समय की नकदी फसल और पूरे साल मांग बनी रहने के नाते उत्तर प्रदेश के किसानों को केले की खेती खूब रास आ रही है। प्रदेश के पूर्वांचल, अवध आदि क्षेत्रों के कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, अमेठी, कौशाम्बी, सीतापुर और लखीमपुर जिलों में केले की खेती होती है।

योगी सरकार द्वारा केले की प्रति हेक्टेयर खेती पर करीब 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। पारदर्शी तरीके से अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों का वितरण और सिंचाई के अपेक्षाकृत प्रभावी ड्रिप और स्प्रिंकलर और सोलर पंप पर मिलने वाले अनुदान के नाते किसानों का क्रेज केले जैसी नकदी फसलों की ओर और बढ़ा है। परंपरागत रूप से केला दक्षिण भारत की फसल है। पर, कुछ दशक पूर्व महाराष्ट्र के भुसावल और इसके आसपास के कुछ इलाकों में इसकी खेती शुरू हुई तो भुसावल और केला (चित्तीदार) एक दूसरे के पर्याय बन गए। देखते-देखते भुसावल का हरी छाल केला पूरे उत्तर भारत के बाजार में छा गया। करीब दो दशक पहले बिहार के नौगछिया के केले ने भुसावल के हरी छाल को लगभग बाजार से बाहर कर दिया। बिहार से सटे कुशीनगर के किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा, लखनऊ से मिले आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में लगभग 3.5 करोड़ मीट्रिक टन केले का उत्पादन होता है। देश में केले

की फसल का रकबा करीब 9,61,000 हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में करीब 70,000 हेक्टेयर रकबे में केले की खेती हो रही है। कुल उत्पादन 3.172 लाख मिट्रिक टन और प्रति हेक्टेयर उपज 45.73 मिट्रिक टन है। केला आर्थिक के साथ धार्मिक और पोषण के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान केले और इसके पत्ते के बिना पूरा नहीं होता। केला रोज के नाश्ते के अलावा व्रत में भी खाया जाता है। केले के कच्चे, पके फल और तने से निकलने वाले रेशे से ढेर सारे सह उत्पाद बनने लगे हैं। बाजार में मौसमी फलों की उपलब्धता सीजन के कुछ महीनों तक रहती है, लेकिन केला उन चुनिंदा फलों में से है जो लगभग पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है। अधिकांश फलों को खाने के लिए धोने, काटने की आवश्यकता होती है लेकिन केले को बिना किसी समस्या के छील कर भी खा सकते हैं।

ग्राहकों के प्याज पर किये गये खर्च का केवल 36 प्रतिशत मिलता है किसानों को: RBI शोध पत्र

आरबीआई के एक शोध पत्र में कहा गया है कि प्याज किसानों को उपभोक्ताओं के खर्च का केवल 36 प्रतिशत मिलता है। वहीं टमाटर के लिए यह 33 प्रतिशत और आलू के मामले में 37 प्रतिशत है। शोध पत्र में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार का सुझाव दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक शोध पत्र में कहा गया है कि प्याज किसानों को उपभोक्ताओं के खर्च का केवल 36 प्रतिशत मिलता है। वहीं टमाटर के लिए यह 33 प्रतिशत और आलू के मामले में 37 प्रतिशत है। शोध पत्र में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार का सुझाव दिया गया है। इसमें किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद के लिए निजी मंडियों की संख्या बढ़ाने की बात शामिल है।

टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को लेकर सब्जियों की महंगाई पर अध्ययन पत्र में कहा गया है, ''चूंकि सब्जियां जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, ऐसे में टमाटर, प्याज और आलू के विपणन में पारदर्शिता में सुधार के लिए निजी मंडियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा से स्थानीय स्तर की कृषि उपज बाजार समिति के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है।'' सकल मुद्रास्फीति पर हाल के दबाव के पीछे खाद्य मुद्रास्फीति को

जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें टमाटर, प्याज और आलू के दाम में भारी उतार-चढ़ाव सबसे चुनौतीपूर्ण रही हैं।

शोध पत्र को आर्थिक अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) के कर्मचारियों तथा बाहर के लेखकों ने मिलकर तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बाजारों में मौजूदा कमियों को कम करने में मदद के लिए ई-राष्ट्रीय कृषि बाजारों (ई-एनएएम) का लाभ उठाया जाना चाहिए। इससे किसानों को प्राप्त कीमतों में वृद्धि होगी जबकि दूसरी तरफ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतें कम होंगी। शोध पत्र में टमाटर, प्याज और आलू के मामले में किसान उपज संगठनों को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। साथ ही प्याज में खासकर सर्दियों की फसल के लिए वायदा कारोबार शुरू करने की वकालत की गयी है। इससे अनुकूलतम मूल्य खोज और जोखिम प्रबंधन में मदद मिलेगी। इसमें इन सब्जियों के भंडारण, उनके प्रसंस्करण और उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों के बारे में सुझाव दिये गये हैं।

वन्यप्राणी क्षेत्रों की सीमा चिन्हित करने बनेगी डिजिटल बाउंड्री

मध्य प्रदेश के वन्यप्राणी क्षेत्रों की सीमा चिन्हित करने के लिए डिजिटल बाउंड्री बनाई जाएगी। डिजिटल बाउंड्री राजस्व विभाग द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें वनमंडलों के डीएफओ सहयोग करेंगे। राजस्व विभाग अपने कम्प्यूटरीकृत नक्शों में यह डिजिटल बाउंड्री प्रदर्शित करेगा। जिससे पता चलेगा कि वन्यप्राणी क्षेत्रों की सीमा के पास ईको सेंसेटिव जोन एवं राजस्व भूमि कहां तक है। आगामी दो माह के अंदर यह डिजिटल बाउंड्री नक्शे में बना दी जाएगी।

इससे यह लाभ होगा कि वन्यप्राणी क्षेत्रों में पर्यटक आवास, रिसोर्ट आदि गतिविधियां स्थापित करने के लिए राजस्व विभाग के कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों में डिजिटल बाउंड्री के जरिए देखा जा सकेगा कि कहां इन गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए वन एवं राजस्व विभाग के बीच सहमति हो गई है तथा आगामी दो माह के अंदर यह डिजिटल बाउंड्री राजस्व विभाग को अपने कम्प्यूटरीकृत नक्शों में प्रदर्शित करना है।

इसलिए पड़ी जरूरत- वन विभाग के अंतर्गत 11 नेशनल पार्क, सात टाइगर रिजर्व और 24 वन्यप्राणी अभयारण्यों में इको सेंसेटिव जोन हैं। वन्यप्राणी क्षेत्रों में खनन एवं निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि ईको सेंसेटिव जोन में निर्माण रेगुलेटेड यानि विनियमित हैं।

विवाद से बचा जा सकेगा- राजस्व और वन भूमि के विवाद के बीच आमजन तो प्रभावित होते ही है, साथ

ही अधिकारी वर्ग भी न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझ जाते हैं। ऐसे में वन क्षेत्र की सीमा तय होने और इसे नक्शे में दर्ज करने से काफी हद तक विवाद की स्थिति से बचा जा सकेगा। इसके अलावा टाइगर रिजर्व और अभयारण्य के सीमा से लगे इको सेंसेटिव जोन में अवैध गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। जंगल की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। यही वजह है कि कमिश्नर, कलेक्टर को ईको सेंसेटिव जोन की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है।

ईको सेंसेटिव जोन की सीमाएं होंगी तय : मध्य प्रदेश के ईको सेंसेटिव जोन की सीमाएं अभी तय नहीं है। टाइगर रिजर्व की बाउंड्री (सीमा) के बाहर कुछ जगह एक किलोमीटर और कई जगह तो एक किलोमीटर के अधिक ईको सेंसेटिव जोन है। कुछ सीमाओं में राजस्व क्षेत्र भी लगा हुआ है। यह सीमाएं राजस्व नक्शे और वन विभाग के नक्शे में भी दर्ज है। चूंकि, अधिकतर कार्य ईको सेंसेटिव जोन में प्रतिबंधित हैं, इस वजह से कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है। अब ईको सेंसेटिव जोन की सीमा तय कर उसे नक्शे में दर्ज कर डिजिटल बाउंड्री बनाई जाएगी। इसके लिए सेटेलाइट इमेज की मदद ली जाएगी।

मध्य प्रदेश की आठ हजार अवैध कालोनियों को दिए जाएंगे स्थायी बिजली कनेक्शन...

मध्यप्रदेश की आठ हजार अवैध कालोनियों के रहवासियों को स्थायी बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने सुगम विद्युत योजना 2024 दो वर्ष के लिए शुरू की है।इस योजना के तहत आवेदक या आवेदकों के समूह को निर्धारित राशि का 25 प्रतिशत आवेदन के साथ एकमुश्त देना होगा।बाकि 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कनेक्शन चालू होने के बाद मासिक बिल के साथ ब्याज सहित देना होगा।यह राशि जमा करने के लिए दो वर्ष का समय तय किया गया है। बता दें कि प्रदेश में दिसंबर 2016 तक छह हजार 77 अवैध कालोनियों को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैध घोषित किया था।इसके बाद से अब तक दो हजार से अधिक अवैध कालोनियों और विकसति हुई है। सुगम विद्युत योजना का लाभ राजधानी की करीब 700 से अधिक अवैध कालोनियों को मिलेगा। इनमें निवास करने वाले पांच हजार से अधिक परिवारों को आसानी से स्थायी कनेक्शन मिल सकेगा।जिससे वह असीमित बिजली बिल से छूटकारा पा सकेंगे। बता दें कि राजधानी में वर्ष 2016 तक बनी 255 अवैध कालोनी वैध की जा चुकी हैं। जबकि वर्ष 2024 तक 450 से

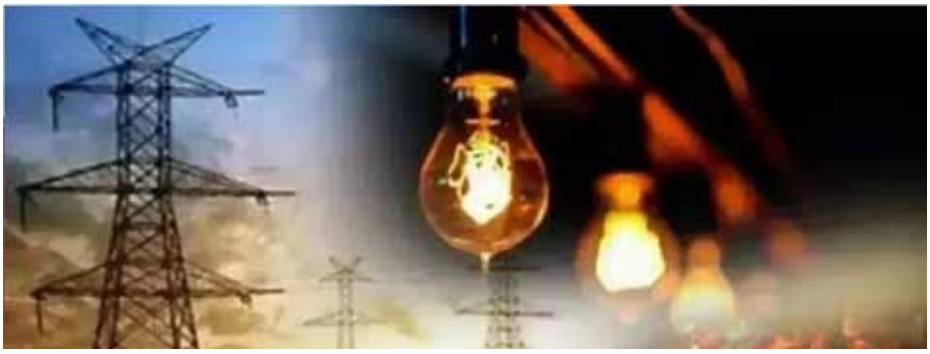

अधिक अवैध कालोनियां विकसित हुई हैं।जिनमें निवास करने वाले रहवासियों के पास अभी अस्थायी कनेक्शन हैं। इस वजह से उनको प्रति महीने पांच हजार रुपये तक बिल जमा करना पड़ता है। **बिल्डर, कालोनाइजर नहीं होंगे पात्र** : मध्य प्रदेश की ऐसी अवैध कालोनियां जो रेरा में पंजीकृत नहीं है। नये आवेदक जो विद्युत कनेक्शन के लिए काम बिजली कंपनी से करवाना चाहते हैं लेकिन लागत राशि का एकमुश्त भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।वह स्थायी कनेक्शन लेने के लिए पात्र होंगे।

जबकि गृह निर्माण संस्था, बिल्डर और कालोनाइजर योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।आवदेन महाप्रबंधक या वृत्त कार्यालय में देना होगा।इसके साथ प्रविधान के अनुसार राशि भुगतान करने का शपथ पत्र भी आवेदक को लगाना होगा।यि तय किश्तों एवं मासिक देयकों का भुगतान नहीं किया गया तो 15 दिन में बिजली कनेक्शन काटा जाएगा।

मध्यप्रदेश में लॉन्च हुआ "संपदा-2.0" पोर्टल

अब घर बैठे कर सकेंगे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में "संपदा-2.0" के शुभारंभ के साथ ही दस्तावेजों की ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली को और सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह प्रणाली ई-रजिस्ट्री और ई-पंजीयन की नई तकनीक पर आधारित है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे ही दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा देना है। इस नई तकनीक से पंजीयन की प्रक्रिया अधिक सुगम, भ्रष्टाचार मुक्त और पेपरलेस हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में "संपदा-2.0" पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से अब लोगों को दस्तावेजों की पंजीयन के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। नागरिक घर से ही ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन और पंजीकरण कर सकेंगे, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

जीआईएस मैपिंग और नई तकनीक का लाभ : मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 120 शहरों की जीआईएस मैपिंग का कार्य सौंपा है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में जीआईएस लैब की स्थापना की जाएगी। इस पहल से राज्य में आईटी के क्षेत्र में भी उन्नति होगी, और पेपरलेस सिस्टम की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

"संपदा-2.0" की खासियतों में से एक यह है कि यह सॉफ्टवेयर राजस्व, वित्त विभाग और नगरीय प्रशासन के साथ जीएसटी और आधार से भी इंटीग्रेटेड है। इसके माध्यम से संपत्ति की जीआईएस मैपिंग, बायोमैट्रिक पहचान और दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग संभव होगी, जिससे पंजीयन की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। डॉ. यादव ने इस अवसर पर कहा कि "संपदा-2.0" का नवाचार जल्द ही देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जाएगा। यह प्रणाली न केवल मध्यप्रदेश में, बल्कि देश के बाहर से भी दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करती है। इस नवाचार से प्रदेश में रजिस्ट्री पंजीयन की प्रक्रिया को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर "संपदा-2.0" का लाभ लेने वाले नागरिकों से वर्चुअल संवाद भी किया। हांगकांग से श्री सुरेन्द्र सिंह चक्रावत और दिल्ली में रहने वाली 78 वर्षीय डॉ. शक्ति मलिक ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने इस नई प्रणाली से घर बैठे दस्तावेजों का पंजीयन कराया। स्पेन के श्री मरियानो मटियास ने बताया कि उनके देश में अभी तक ई-रजिस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई है, और उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की इस पहल की सराहना की। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इस अवसर पर कहा कि "संपदा-2.0" के माध्यम से मध्यप्रदेश देश में रजिस्ट्री पंजीयन की डिजिटल प्रक्रिया में अग्रणी बन गया है। यह पहल राज्य में नागरिकों के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित होगी और उन्हें पंजीयन की पारदर्शी और सरल प्रणाली का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया।

चंबल नदी किनारे ले सकेंगे ऊंट सफारी का लुत्फ

चंबल नदी और बीहड़ पर्यटकों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। अब पर्यटक नदी किनारे ऊंट सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। दूर-दूर तक फैले रेत, कल-कल करता चंबल का पानी, तेज हवा के झोंके का आनंद पर्यटक कैंपिंग करके ले सकेंगे। पर्यटन विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। वन विभाग की देखरेख में इसको विकसित किया जाएगा। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि नवंबर माह से नदी किनारे सफारी शुरू कराए जाने की योजना है। जिले की अटेर तहसील में चंबल नदी किनारे ऐतिहासिक किले के पास ऊंट सफारी शुरू कराए जाने को लेकर जगह चिह्नित की गई है। ऊंट सफारी के साथ-साथ यहां खाने-पीने की चीजों के स्टाल भी लगाए जाएंगे। इस सफारी में सैलानी रात के समय चंबल नदी किनारे रुक कर प्रकृति का आनंद ले सकेंगे।

ऋषिकेश की तरह होगी कैंपिंग : जिस तरह से उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी किनारे कैंपिंग की जाती है, उसी तर्ज पर चंबल नदी किनारे कैंपिंग शुरू कराए जाने की योजना है। कैंप में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पर्यटक सर्दियों में अलाव के बीच संगीत के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे।

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सफारी में ऊंट रखे जाने को लेकर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह से सफारी में खाने-पीने सहित अन्य के स्टाल लगाने की योजना है। अटेर में सफारी शुरू होने से एक तरफ जहां रोजगार के अवसर पर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

▶ अटेर में ऊंट सफारी शुरू कराए जाने को लेकर पर्यटन विभाग ने अनुमति दे दी है। फिलहाल नवंबर माह में सफारी शुरू कराए जाने की योजना तैयार की गई है।

-मोहम्मद माज, वन मंडलाधिकारी

करवा चौथ का त्यौहार मनाया बड़े उत्साह के साथ... महिलाओं ने की खरीदारी...

करवा चौथ पर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर भगवान से पति की लम्बी उम्र की कामना की।

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीप पर्व... मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की...

'जल ही जीवन' पर गरमाई सियासत

विपक्ष ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार को घेरा...

जल जीवन मिशन के तहत सरकार जहां एक तरफ हर घर में नल से जल पहुंचाने के अभियान में जुटी हुई है, वहीं योजना को लेकर राजनीति भी चरम पर है। दरअसल, फंड के अभाव में कई जगह काम रूका हुआ है। वहीं कई जगह स्थिति यह है कि योजना कुप्रबंधन का शिकार हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने सीएम डॉ. मोहन यादव की ओर से केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल को लिखा एक पत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें सीएम ने लिखा है कि बजट न मिलने से 'हर घर नल' से जुड़े काम नहीं हो पा रहे। इस वित्तीय वर्ष में मप्र को 2022.34 करोड़ रु. आवंटित किए गए, पर मिले नहीं। पानी से जुड़ी जरूरतों के लिए 4455.30 करोड़ रुपए अलग से मांगे हैं। कांग्रेस का दावा है क सीएम ने यह पत्र पिछले महीने 13 सितंबर को लिखा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'अगस्त 2019 में पीएम ने बड़ी धूमधाम से जल जीवन मिशन की घोषणा की। मार्च 2024 तक देश के सभी घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया गया, पर अब तक वादा पूरा नहीं किया गया।'

जल जीवन मिशन के तहत गांवों में लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है। जल कितने घरों तक पहुंचा, कितना लक्ष्य बाकी है। काम में कहां खामी है, क्या शिकायतें हैं और क्या समाधान... यह सब मसले सियासत की वजह से पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में मिशन का काम कर रहे ठेकेदारों के करीब 1500 करोड अटके हैं। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में उल्लेख है कि पिछले वित्त वर्ष में 10773.41 करोड़ खर्च किए गए। मौजूदा समय में 1500 करोड़ का भुगतान लंबित है। ऐसे में इस वित्त वर्ष में लंबित भुगतान को मिलाकर 17000 करोड रुपए की आवश्यकता बताई गई है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के अलावा भाजपा विधायक भी मामला विधानसभा में उठा चुके हैं। सांची से भाजपा विधायक डॉ. प्रमुराम चौधरी ने कहा था, अफसरों की लापरवाही से 150 से ज्यादा गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा। भाजपा विधायक हरदीप सिंह डंग, कालू सिंह ठाकुर, संजय पाठक, अंबरीष शर्मा ने भी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था।

मिशन में घोर लापरवाही...

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि मिशन की नाकामी केंद्र सरकार की घोर लापरवाही का परिणाम है। इस कारण प्रदेश की जनता को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 14 फरवरी 2024 को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी विधानसभा में जेजेएम के 20 करोड़ के घोटाले को उजागर किया था। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि जयराम रमेश अपने कार्यकाल को याद करें जनता कैसे पानी के लिए तरसती थी। आज भाजपा की सरकार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हर घर नल से जल पहुंच रहा है। मप्र आइए, गांव- गांव घूमिए और देखिए नल से कैसे लोग पानी पीते हैं। आज मप्र में 71 लाख पांच हजार घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। पीएचई के प्रमुख अभियंता केके सोनगरिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंड सबसे जरूरी है, इसलिए समय रहते चिंता कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश सरकार की योजना, हर माह मिलेंगे आठ हजार रुपए...

मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने अपनी एकलव्य शिक्षा विकास योजना का विस्तार करते हुए ये नए प्रावधान किए

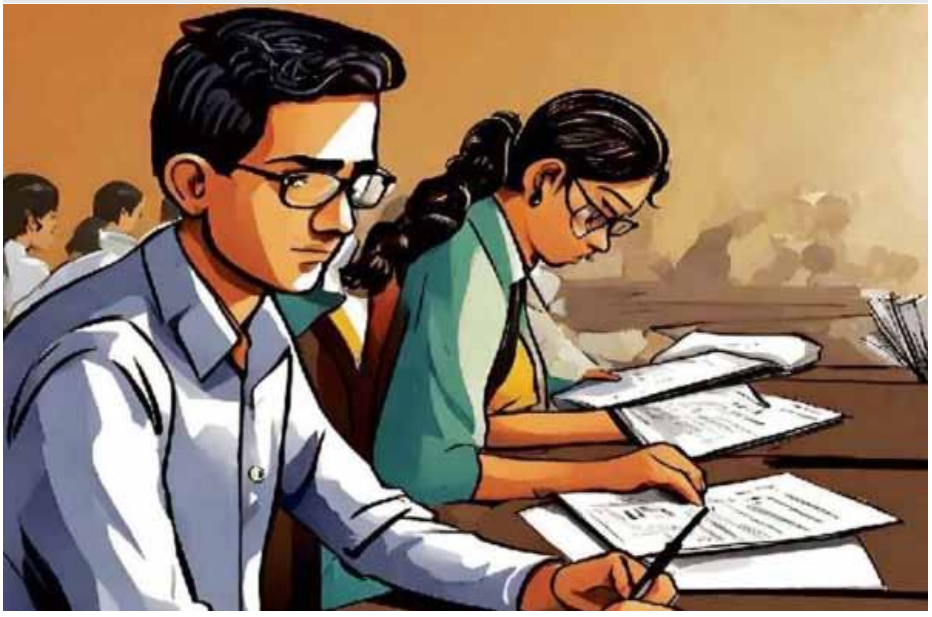

मध्य प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों के मेधावी बच्चों को राज्य सरकार इंजीनियरिंग, ला और मेडिकल कोर्स की कोचिंग कराएगी। इसके लिए मेधावी बच्चों को कोचिंग का भत्ता भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने अपनी एकलव्य शिक्षा विकास योजना का विस्तार करते हुए यह नए प्रविधान किए हैं।

इसके अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के प्रबंधकों के मेधावी बच्चों को इसी वर्ष से 12वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने पर व्यावसायिक कोर्स जैसे इंजीनियरिंग एवं विधि (ला) और मेडिकल की कोचिंग के लिए भत्ता दिया जाएगा।

12 माह तक आठ हजार रुपये प्रति माह- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा संभागीय मुख्यालयों के लिए 12 माह तक आठ हजार रुपये प्रति माह, अन्य संभागीय मुख्यालयों के लिए छह हजार रुपये प्रति माह तथा संभागीय जिलों को छोड़कर शेष अन्य जिलों के लिए 3500 रुपये प्रति माह कोचिंग भत्ता दिया जाएगा।

नौवीं से स्नातक तक पढ़ाई में आर्थिक मदद करता है संघ लघुवनोपज संघ- वर्ष 2022-23 से एकलव्य शिक्षा योजना के तहत कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 15 हजार रुपये, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को 18 हजार रुपये, गैर तकनीकी स्नातक उपाधि प्राप्त अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए 25 हजार रुपये एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 60 हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करता है। अब इंजीनियरिंग, ला और मेडिकल जैसी डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए कोचिंग में भी मदद की जाएगी।

मप्र में 16 लाख परिवारों के 41 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक-मध्य प्रदेश में वनोपज तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले 16 लाख परिवार है और इनमें कुल 41 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक है। इनमें अधिकांश तेंदूपत्ता संग्राहक आदिवासी परिवार है जो जंगल से सटे गांवों में निवास करते हैं और केवल वन संपदा पर ही निर्भर हैं। राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी समय-समय पर आदिवासी परिवारों के उत्थान के लिए दिशा-निर्देश देते आए हैं। राज्यपाल की पहल ही वन विभाग इस दिशा में आगे बढ़कर पहल की है।

सृष्टि आरंभ दिवस के रूप में मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा

कालिदास समारोह में पुरस्कार राशि बढ़ेगी

मध्य प्रदेश में 30 मार्च को गुडी पड़वा पर्व को उज्जैन के साथ पूरे प्रदेश में विक्रम पर्व सृष्टि आरंभ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगम में विज्ञान और खगोल विषय से जुड़े विशेषज्ञों को विक्रमोत्सव में आमंत्रित किया जाए। इससे आयोजन की गरिमा बढ़ेगी और प्रदेश के युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। महोत्सव में होने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को विक्रमादित्य पर केंद्रित किया जाए और कविताओं को लेखबद्ध करें। कालिदास समारोह के दौरान दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि में वृद्धि की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में विक्रमोत्सव-2025, अखिल भारतीय कालिदास समारोह और वीर भारत न्यास द्वारा निर्मित किए जा रहे संग्रहालय की समीक्षा करते हुए दिए।

उन्होंने कहा कि विक्रमोत्सव 2025 और अखिल भारतीय कालिदास समारोह को भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। इसमें अतिथियों और विद्यार्थियों को महाकाल देवदर्शन के साथ उज्जैन के इतिहास, विज्ञान, संस्कृति और मूल्यों से परिचय कराया जाए। कालिदास संस्कृत अकादमी की केंद्रीय समिति की बैठक में बताया कि समारोह की शुरुआत गढ़कालिका मंदिर से दस नवंबर को वागअर्चन के साथ होगी। अभी पांच से लेकर दो लाख रुपये अलग-अलग पुरस्कार में दिए जाते हैं। 12 से 18 नवंबर तक होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित करने पर चर्चा हुई। चूंकि, उस अवधि में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं इसलिए उप राष्ट्रपति को आमंत्रित करने पर विचार किया गया। डा.यादव ने कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को देखते हुए स्थायी अधोसंरचना विकास पर जोर दिया ताकि बार-बार खर्च न हो।

मध्य प्रदेश में इसी माह घोषित हो सकती है तबादला नीति

जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की मांग को देखते हुए मोहन यादव सरकार इसी माह तबादला नीति घोषित कर सकती है। इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी है। तबादलों पर पिछले डेढ़ साल से प्रतिबंध है। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनाव के चलते तबादले नहीं हो पाए हैं। तब से लेकर बड़े पदों पर अब तक केवल मुख्यमंत्री के समन्वय से ही तबादले हो रहे हैं। अब दोनों ही चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तबादले से रोक हटाने जा रही है।

प्रस्तावित नीति में प्रावधान किया गया है कि प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही तबादले किए जाएंगे। इसके लिए सरकार के प्राथमिकता वाले जिलों का प्रभार वरिष्ठ मंत्रियों को दिया गया है। 2022 में तबादलों से रोक हटी थी। इसके बाद अब नई नीति के तहत तबादले किए जाएंगे। एक जिले से दूसरे जिले के लिए स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर तबादले किए जाएंगे, लेकिन ये 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

- जहां भाजपा का कमजोर जनाधार, उन जिलों में वरिष्ठ मंत्रियों को दिया प्रभार
- मध्य प्रदेश के जिन जिलों में भाजपा का कमजोर जनाधार रहा है वहां प्रभार वरिष्ठ मंत्रियों को दिया गया है।
- वे प्रभार के जिलों में सरकार और पार्टी दोनों के बीच तालमेल बनाते हुए कार्य कर रहे हैं।
- तबादलों में भी यह तालमेल देखने को मिलेगा।
- इंदौर जैसा महत्वपूर्ण जिला मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास रखा है।
- भोपाल का प्रभार मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप को दिया गया है। छिंदवाड़ा जिला का प्रभार राकेश सिंह के पास है।
- ऐसे ही महत्वपूर्ण जिलों की कमान वरिष्ठ मंत्रियों को सौंपी गई है।

पहले मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और अब बिहार में भी चुनाव लड़ेगी आप

आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रही है। ये ऐलान भी उस समय हुआ है जब मुंबई में विपक्षी एकता की तीसरी अहम बैठक होने जा रही है।

आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में कई राज्यों तक अपना विस्तार कर लिया है। दिल्ली के बाद उसने पंजाब में सरकार बनाई है, गुजरात में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी किस्मत आजमाने जा रही है। अब इसी कड़ी में खबर है कि आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रही है। ये ऐलान भी उस समय हुआ है जब मुंबई में विपक्षी एकता की तीसरी अहम बैठक होने जा रही है।

असल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। उस बैठक के बाद ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने बताया कि पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ेगी।

उनके मुताबिक वर्तमान में बिहार में पार्टी के पास मजबूत संगठन नहीं है, लेकिन बड़ी तादात में नेता मौजूद हैं। उनके मुताबिक बिहार में किसी को भी राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है, 10 साल के बच्चे तक को सब समझ आता है। जोर देकर कहा गया है कि चुनाव लड़ने या ना लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, चुनाव में तो उतरना ही पड़ेगी।

अब आम आदमी पार्टी के इस एक ऐलान ने इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी है। आरजेडी नेता और सांसद मनोज झा ने दो टूक कहा है कि जिस समय विपक्षी एकता की नींव रखी गई थी, ये साफ किया गया था कि सभी पार्टियों को कुछ नियमों को पालन करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आम आदमी पार्टी भी उन सिद्धांतों का पालन करेगी। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए बिहार कोई पहला राज्य नहीं है जहां वो दूसरे दलों के विरोध के बीच उतरने की बात कर रही हो।

एमपी-छत्तीसगढ़ में भी बिगाड़ा खेल

कुछ दिन पहले ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में उनकी तरफ से कांग्रेस पर निशाना भी साधा गया। इसी कड़ी में दिल्ली में कांग्रेस ने भी तल्ख तेवर दिखाते हुए कह दिया कि सातों सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि हर तरफ इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती वाली स्थिति बन रही है।

5वी और 8वीं की परीक्षा मार्च में संभावित, वस्तुनिष्ठ व अति लघुत्तम प्रश्न होंगे

प्रत्येक विषय में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी, जबकि वस्तुनिष्ट व अति लघुउत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक होगी...

मप्र बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूलों की पांचवीं व आठवीं की वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित किए जाने की संभावना है। राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पांचवीं व आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा कराने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा परिणाम के लिए अधिभार अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अधिभार अंक 20, वार्षिक परीक्षा लिखित अधिभार अंक 60 और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य के लिए अधिभार अंक 20 निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक विषय में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी, जबकि वस्तुनिष्ट व अति लघुउत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक होगी।

निर्देश में कहा गया है कि सभी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा द्वारा निर्धारित ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयार कराए गए प्रश्न-पत्रों और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही कराया जाएगा। सरकारी स्कूलों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र राज्य स्तर से तैयार कराए जाएंगे, जबकि निजी स्कूल निर्धारित ब्लू प्रिंट के आधार पर प्रश्न-पत्रों को स्वयं तैयार कराएंगे।

सरकारी स्कूलों में भाषा विषय (हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत) की राज्य स्तर के एससीईआरटी पाठ्यपुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं निजी स्कूलों में अगर एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें लागू हैं तो उनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अन्य विषयों के प्रश्नपत्र भी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक से ही पूछे जाएंगे। 33 प्रतिशत अंक लाना होगा- प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन में अलग-अलग न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा में शामिल होना होगा। पुनः परीक्षा में भी फेल होने वाले विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोका जाएगा।

परीक्षा अंक योजना छमाही परीक्षा -अधिभार 20 अंक वार्षिक परीक्षा(लिखित) -60 अंक आंतरिक मूल्यांकन (प्रोजेक्ट कार्य) -20 अंक -- इस तरह के होंगे लिखित परीक्षा के प्रश्नों के पैटर्न बहु विकल्पीय प्रश्न-पांच अंक(पांच प्रश्न) रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न-पांच अंक(पांच प्रश्न) अति लघुउत्तरीय प्रश्न -12 अंक (छह प्रश्न) लघु उत्तरीय प्रश्न -18 अंक (छह प्रश्न) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-20 अंक (चार प्रश्न)।

मानसून अच्छा होने से टूटेगा गेहूं की बोवनी का रिकॉर्ड

प्रदेश में इस बार मानसून अच्छा रहने से गेहूं का बोवनी का रिकार्ड भी टूटेगा। अभी तक अधिकतम 95 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई है। इस बार 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बढ़कर 110 लाख हेक्टेयर पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने खाद-बीज को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले सप्ताह से होने वाली कृषि उत्पादन आयुक्त की संभागीय बैठकों में लक्ष्य निर्धारित हो जाएंगे। प्रदेश में अकेले रीवा जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में औसत से अधिक वर्षा हुई है। इससे रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं का क्षेत्र बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में 97.81 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोवनी हुई थी, जो 2023-24 में घटकर 92.10 लाख हेक्टेयर रह गई थी, यानी गेहूं का क्षेत्र 5.84 प्रतिशत घट गया था। यह फिर बढ़कर 95 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच गया।

गेहूं का क्षेत्र बढ़ने की अनुमान : इस बार वर्षा की स्थिति को देखते हुए कम जोखिम वाली फसल गेहूं का क्षेत्र बढ़ने की अनुमान लगाया जा रहा है। मालवांचल, मध्य भारत और महाकोशल अंचल में क्षेत्र बढ़ने की अधिक संभावना है क्योंकि यहां सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता अधिक है। चना का क्षेत्र भी लगातार बढ़ रहा है। यह 2022-23 में 21 लाख हेक्टेयर था जो 2023-24 में बढ़कर 23.46 लाख हेक्टेयर हो गया। इसमें भी वृद्धि हो सकती है। रबी फसलों का क्षेत्र बढ़ने के अनुमान के आधार पर मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने भारत सरकार से अक्टूबर-नवंबर में अतिरिक्त डीएपी, एनपीके, कम्प्लेक्स और बीज की आपूर्ति बढ़ाकर करने का अनुरोध किया है। उपार्जन में पंजाब को पीछे छोड़ चुका है मप्र : प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार गेहूं का उपार्जन करती है। गत वर्ष बाजार में अधिक मूल्य मिलने के कारण उपार्जन कम हुआ था। जबकि, 2020-21 में पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश उपार्जन में देशभर में अव्वल रहा था। यहां के शरबती गेहूं की देश-दुनिया में मांग रहती है।

राजस्थान विधानसभा उपचुनाव गढ़ बचाने में लगी पार्टियां...

जिन सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे है। उनमें से प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के पास सिर्फ एक सलूंबर की सीट थी। जहां उनके लगातार तीन बार के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के चलते उपचुनाव हो रहा है। भाजपा के लिए सलूंबर की सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है।

राजस्थान में आगामी 13 नवंबर को सात विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। सात में से पांच विधानसभा सीटों झुंझुनू, दौसा, खींवसर, देवली-उनियारा, चौरासी में वहां के विधायकों के सांसद बनने के चलते इस्तीफा देने से उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं सलूंबर व रामगढ़ में विधायकों की मृत्यु होने के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि इन विधानसभा उपचुनावो के नतीजों से प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इससे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को कोई खतरा होने वाला नहीं है। मगर इन उपचुनाव के नतीजे का असर प्रदेश की राजनीति में कई पार्टियों व उनके नेताओं के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में सात विधानसभा सीटों में से चार सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। वही एक सीट पर भाजपा, एक पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) व एक पर भारतीय आदिवासी पार्टी (बाप) का विधायक था।

जिन सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे है। उनमें से प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के पास सिर्फ एक सलूंबर की सीट थी। जहां उनके लगातार तीन बार के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के चलते उपचुनाव हो रहा है। भाजपा के लिए सलूंबर की सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इसीलिए भाजपा ने दिवंगत विधायक की पत्नी शांता मीणा को टिकट देकर सहानुभूति का लाभ उठाना चाहती है। इसके अलावा प्रदेश की अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी है।

उपचुनाव में हार जीत के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बहुत अच्छा नहीं रहा था। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि सभी सात सीटों पर उपचुनाव में उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनवाकर भाजपा आला कमान की नजरों में अपनी मजबूत छवि बना सके। भाजपा प्रदेश की सभी सातों सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने समय रहते अपने सभी बागियों को मना कर एकजुटता का संदेश देने में सफल रही है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ उतरे बागियों को चुनाव से हटाने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास सफल रहे हैं।

प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के उपचुनाव में विजय हासिल करने के चक्कर में भाजपा ने अपनी नीति व सिद्धांतों को भी ताक पर रख दिया है। दौसा सीट पर राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोडीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। जबकि दौसा सीट सामान्य वर्ग की सीट है। मगर भाजपा ने डॉक्टर किरोडीलाल मीणा के दबाव में अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। डॉक्टर किरोडीलाल मीणा के भतीजे राजेन्द्र मीणा भी महुआ से विधायक है। इस तरह एक परिवार के तीन लोगों को पार्टी ने टिकट देकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है।

वही 2023 के विधानसभा चुनाव में झुंझुनू से भाजपा के प्रत्याशी निशित कुमार उर्फ बबलू के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र भांभू व रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सुखवंत सिंह को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। देवली-उनियारा सीट पर भी भाजपा ने पिछली बार चुनाव लड़े कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला का टिकट काटकर पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है। वहीं खींवसर सीट पर रालोपा के अध्यक्ष व नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को पिछले विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देकर मात्र 2059 वोटो से हारने वाले रेवतराम डागा को फिर से मैदान में उतारा है।

चौरासी सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की करारी हार हुयी थी। इस बार भाजपा ने वहां नया प्रत्याशी कारीलाल ननोमा को मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी सीमलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान है तथा सादड़िया के सरपंच रह चुके हैं। अब उनकी पुत्रवधू रेखा सरपंच है। उनकी पत्नी हाकली देवी भी सरपंच रह चुकी है। क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के कारण राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस बार वहां भाजपा कड़ी टक्कर दे सकती है।

कांग्रेस को अपनी चार सीट झुंझुनू, दौसा, देवली-उनियारा व रामगढ़ फिर से जितनी होगी। साथ ही अन्य तीन सीटों पर भी अपनी ताकत दिखानी होगी कांग्रेस ने झुंझुनू सें सांसद बने बृजेंद्र सिंह ओला के बेटे अमित ओला को मैदान में उतारा है। अमित ओला ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी है तथा उनके दादा शीशराम ओला झुंझुनू से पांच बार सांसद नौ बार विधायक केंद्र तथा राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। वहीं रामगढ़ सीट पर दिवंगत विधायक जुबेर खान के पुत्र आर्यन खान को उतार कर सहानुभूति के बल पर चुनाव जीतना चाहती है।

दौसा सामान्य सीट पर कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के दीनदयाल बैरवा को टिकट देकर मैदान में उतारा है। देवली-उनियारा से पूर्व अधिकारी कस्तूर चंद मीणा को मैदान में उतारा है। यहां कांग्रेस के बागी नरेश मीणा चुनाव को त्रिकोणात्मक बना रहे हैं। नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी मनाने में नाकाम रही है। जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं मानी जा रही है।

सलूंबर में कांग्रेस ने 2018 में निर्दलिय चुनाव लड़कर कांग्रेस को हराने वाली रेशमा मीणा को मैदान में उतारा है। जिससे नाराज होकर सांसद, विधायक व मंत्री रह चुके रघुवीर मीणा अंदर खाने पार्टी प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चौरासी सीट पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार 29 साल के नए प्रत्याशी महेश रोत को मैदान में उतारा है। खींवसर सीट पर कांग्रेस पार्टी ने महिला प्रत्याशी रतन चैधरी को मैदान में उतार कर हनुमान बेनीवाल के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। जिसका फायदा भाजपा को हो सकता है।

पति यौन इच्छा पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा तो कहां जाएगा : हाई कोर्ट

एक व्यक्ति के खिलाफ दहेज के आरोपों को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये आरोप निराधार हैं और व्यक्तिगत विवादों से प्रेरित हैं। अदालत ने इस मामले में कहा कि नैतिक रूप से सभ्य समाज में व्यक्ति यौन इच्छा अपनी पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा तो कहां जाएगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ दहेज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये आरोप निराधार हैं और व्यक्तिगत विवादों से प्रेरित हैं। अदालत ने इस मामले में कहा कि नैतिक रूप से सभ्य समाज में व्यक्ति यौन इच्छा अपनी पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा तो कहां जाएगा। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने प्रांजल शर्मा और दो अन्य के खिलाफ इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि प्राथमिकी में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान, दहेज के लिए उत्पीड़न के दावों का समर्थन नहीं करते। अदालत ने पाया कि प्राथमिक आरोप, दंपति के यौन संबंध से जुड़ी असहमतियों के आसपास केंद्रित हैं और ये विवाद दहेज की मांग से जुड़े नहीं हैं। अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच यह विवाद यौन संबंध स्थापित नहीं होने को लेकर है जिसकी वजह से विपक्षी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई और दहेज की मांग को लेकर झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप लगाए गए।" अदालत ने प्रश्न किया, "नैतिक रूप से सभ्य समाज में व्यक्ति यौन इच्छा अपनी पत्नी से या पत्नी अपनी यौन इच्छा पति से व्यक्त नहीं करेगी तो वे कहां जाएंगे।" प्राथमिकी में प्रांजल शुक्ला पर दहेज की मांग करने और पत्नी से गाली गलौज करने के साथ ही उसे अश्लील फिल्में देखने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया हैं। अदालत ने कहा कि विश्वसनीय साक्ष्य से ये आरोप साबित नहीं हुए।

इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, मीशा शुक्ला का विवाह आवेदक प्रांजल शुक्ला के साथ हिंदू रीति रिवाज से सात दिसंबर, 2015 को हुआ था। मीशा ने अपने सास-ससुर मधु शर्मा और पुण्य शील शर्मा पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। हालांकि, प्राथमिकी में यह भी स्पष्ट किया गया कि शादी से पहले दहेज की कोई मांग नहीं थी। प्राथमिकी में यह भी बताया गया कि प्रांजल शराब पीता और अश्लील फिल्में देखता। साथ ही वह अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर जोर देता और मना करने पर वह उस पर ध्यान नहीं देता। बाद में वह अपनी पत्नी को छोड़कर सिंगापुर चला गया। याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विनय शरण ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप और विपक्षी के बयान शारीरिक संबंध को लेकर हैं और विपक्षी (पत्नी) द्वारा बयान में मारपीट को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वे याचिकाकर्ता की यौन इच्छा पूरी नहीं करने के संबंध में हैं ना कि दहेज की मांग के लिए। अदालत ने कहा, "प्राथमिकी और पीड़िता के बयान पर गौर करने से साफ है कि यदि कोई मारपीट की गई तो वह दहेज की मांग के लिए नहीं, बल्कि यौन इच्छा पूरी करने से मना करने के लिए की गई।" अदालत ने तीन अक्टूबर को दिए अपने आदेश में शुक्ला के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, "हमारे विचार से मौजूदा प्राथमिकी कुछ और नहीं बल्कि दहेज की मांग को लेकर मनगढ़ंत कहानी है।

राजस्थान में कांग्रेस सक्षमता से चुनाव लड़ेगी, हरियाणा से नहीं पड़ेगा कोई असर

हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के कई नेता भाजपा पर ईवीएम हैक करने का आरोप लगा रहे हैं, तो कई नेताओं ने हरियाणा में धोखाधड़ी करने तक का आरोप-प्रत्यारोप लगाया है। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने कहा कि हरियाणा चुनाव से राजस्थान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

राजस्थान में कांग्रेस इस बार सक्षमता से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल भी करेगी। राजस्थान में कुछ सीटों पर उपचुनाव है। जिसको लेकर सियासी पार्टी अपना दांव पेंच लगा रही हैं। पायलट ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में सभी सीट पर मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी।

उन्होंने कहा, "राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में सभी सीट पर कांग्रेस जीतेगी। हम लोगों ने बहुत पहले से अपनी तैयारी कर रखी है।" कांग्रेस नेता ने कहा, ''मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा के चुनाव का बहुत ज्यादा प्रभाव इन उपचुनावों पर पड़ेगा क्योंकि अलग राज्य है।

अलग परिस्थिति में यह उपचुनाव हो रहा है। मैं समझता हूं सात सीट पर उपचुनाव होगा और सभी सीट पर कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी यह मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। पायलट ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट 'शेयर' बढ़ा है और मैं समझता हूं कि जितने वोट भाजपा को मिले उतने ही हम लोगों को मिले तो हमारा वोट बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का मत प्रतिशत घटा है लेकिन इसका कोई नकारात्मक प्रभाव बाकी राज्यों मे पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि महाराष्ट्र में एक मजबूत गठबंधन पहले से है और झारखंड में भी गठबंधन काफी मजबूत है।

बड़े दिग्गज चेहरों को चुनाव में हार का करना पड़ा सामना

हरियाणा में कई बार मुख्यमंत्री रहे देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल के वंशजों को भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। बताते हैं हरियाणा के दस ऐसे बड़े दिग्गज चेहरों के बारे में जो इस बार चुनाव हार गई है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी, कांग्रेस, INLD and JJP के कई दिग्गज चेहरों को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने बहुमत तो हासिल कर ली लेकिन कई बड़े नेता जिनसे अच्छे प्रदर्शन के कयास लगाए जा रहे थे वो हार गए। ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, डॉ कमल गुप्ता और सुनीता दुग्गल जैसे सीनियर नेताओं को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा में कई बार मुख्यमंत्री रहे देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल के वंशजों को भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। बताते हैं हरियाणा के दस ऐसे बड़े दिग्गज चेहरों के बारे में जो इस बार चुनाव हार गई है।

दुष्यंत चौटाला

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना से इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। दुष्यंत चौटाला सिर्फ 7,950 वोट मिले हैं।

भव्य बिश्नोई

भजनलाल की पुश्तैनी सीट आदमपुर से बीजेपी की टिकट पर भव्य बिश्नोई को कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश से 1268 वोटों से इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है।

बृजेंद्र सिंह

बीरेंद्र सिंह के बेटे उचाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को भाजपा प्रत्याशी से महज 32 वोटों से हार का सामना करना पड़ा।

रणजीत चौटाला

बीजेपी सरकार में बगैर विधायक बने अंतिम समय तक मंत्री रहे रणजीत चौटाला भी अपनी छवि का करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं।

ज्ञान चंद गुप्ता

पंचकूला से पूर्व विस अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे चंद्रमोहन से हार का सामना करना पड़ा है।

कंवर पाल गुर्जर

हरियाणा की जगाधरी विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर को कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी अकरम खान ने 6868 वोट से मात दी।

डॉ. कमल गुप्ता

हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और निवर्तमान विधायक कमल गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल से हार गए हैं।

गोपाल कांडा

सिरसा से गोपाल कांडा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल था।

सुनीता दुग्गल

फतेहाबाद की रतिया सीट से बीजेपी की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल कांग्रेस के प्रत्याशी जरनैल सिंह से 21442 मतों के अंतर से चुनाव में हार गई।

अभय चौटाला

देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला ऐलनाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल से 15000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। अभय चौटाला को 62,865 वोट मिले थे।

हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा : मोहन भागवत

भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने कहा कि भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। भागवत ने शनिवार शाम को राजस्थान के बारां में 'स्वयंसेवक एकत्रीकरण' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''हम यहां प्राचीन काल से रह रहे हैं, भले ही हिंदू शब्द बाद में आया। हिंदू सभी को गले लगाते हैं। वे निरंतर संवाद के माध्यम से समरसता के साथ रहते हैं।''

उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय विवादों को दूर कर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा, ''आचरण में अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण आवश्यक गुण हैं। एक समाज केवल व्यक्तियों और उनके परिवारों से नहीं बनता है, बल्कि उन व्यापक चिंताओं पर विचार करने से बनता है जिनके माध्यम से कोई आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, ''आरएसएस की कार्यप्रणाली यात्रिक नहीं बल्कि विचारों पर आधारित है। यह एक अद्वितीय संगठन है जिसके मूल्य समूह के नेताओं से लेकर स्वयंसेवकों, उनके परिवारों और बड़े पैमाने पर समाज से मिलते हैं।'' स्वयंसेवकों से समुदायों के भीतर व्यापक संपर्क बनाए रखने का अनुरोध करते हुए भागवत ने कहा कि समाज को सशक्त बनाकर सामुदायिक कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

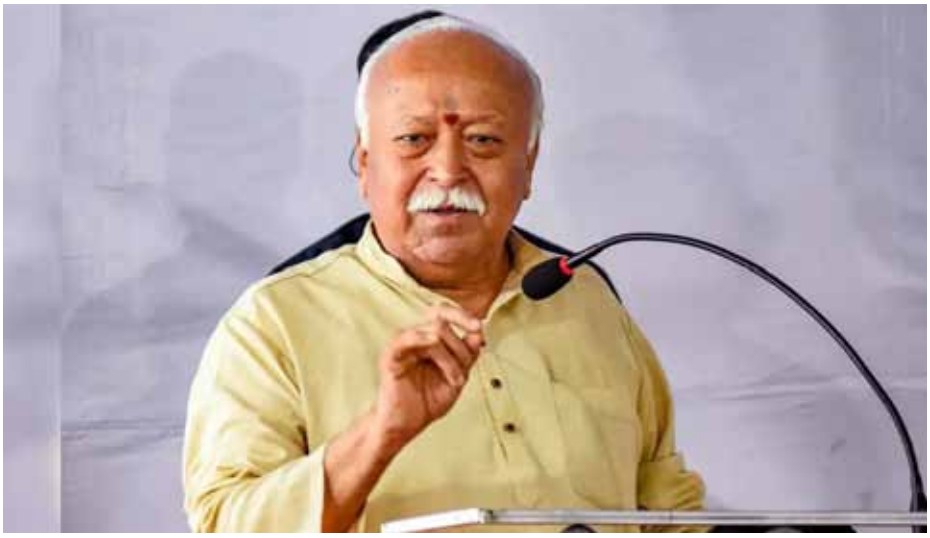

भागवत ने कहा, ''सामाजिक समरसता, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। स्वयंसेवकों को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और परिवारों के भीतर सौहार्द, पर्यावरण जागरूकता, स्वदेशी मूल्यों और नागरिक चेतना को बढ़ावा देना चाहिए, जो किसी समाज के बुनियादी घटक हैं।''

उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक साख और प्रतिष्ठा का श्रेय इसकी ताकत को जाता है और इसके प्रवासियों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब उनका राष्ट्र मजबूत बने। कुल 3,827 आरएसएस स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी रमेश अग्रवाल, जगदीश सिंह राणा, रमेश चंद मेहता और वैद्य राधेश्याम गर्ग भी शामिल हुए।

कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने चुनावी मैदान में दी पटखनी, 'आप' की हुई जमानत जप्त

ओलंपिक खिलाड़ी एवं पहलवान विनेश फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में सबको पटखनी देते हुए जीत हासिल की है। कांग्रेस उम्मीदवार फोगाट ने हरियाणा में जुलाना विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव जीत लिया और भारतीय जनता पार्टी के योगेश कुमार को 6,015 मतों के अंतर से हराया। ओलंपिक में पदक से चुकने के बाद भारत लौटने पर विनेश ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर राजनीति का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही विनेश कांग्रेस में शामिल हुईं और पार्टी ने जुलाना से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। जुलाना विनेश फोगाट का ससुराल है। हरियाणा में पांच अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना मंगलवार को सुबह आठ बजे शुरू हुई।

कभी अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे और कभी पीछे हुईं विनेश को कुल 65,080 मत हासिल हुए, वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के योगेश को 59,065 मत मिले। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कविता दलाल केवल 1,280 मत ही हासिल कर सकीं और उनकी जमानत जब्त हो गई। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो)

और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी डॉ. सुरेंद्र लाठर ने 10,152 मत हासिल किए और जननायक जनता पार्टी (जजपा) से विधायक रहे अमरजीत ढांडा केवल 2,477 मत हासिल कर सके।

रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर कसा तंज

डायनासोर वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं...

हरियाणा में सरकार बनाने की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस पार्टी की हार और दस साल बाद भी सत्ता से दूर रहने पर कई तरह की सियासी चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "डायनासोर वापिस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिलकुल नहीं आ सकती।" उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर भी इसको लेकर पोस्ट किया है।

रवनीत सिंह बिट्टू खुद पहले कांग्रेस में रहे हैं। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया था, हालांकि वह हार गए। इसके बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया। हाल ही में वह राज्यसभा सदस्य बने हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब कभी सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कुछ दिनों पहले अमेरिका में सिखों की पगड़ी को लेकर राहुल गांधी के बयानों की भी तीखी निंदा की थी।

रवनीत सिंह ने दूसरों को नसीहत देने पर भी कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर ही नसीहत देनी चाहिए। उन्हें अपने नेता राहुल गांधी के बयानों को देखना चाहिए। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी।

हरियाणा में इस बार बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई है। पार्टी को विधानसभा में 90 में से 48 सीटों पर सफलता मिली है। कांग्रेस पार्टी को केवल 35 सीटें ही मिली हैं। बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से अपनी

सरकार बनाएगी। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पार्टी को मिली यह सफलता दूसरे राज्यों के लिए भी जीत का रास्ता बनेगी।

उधर, हरियाणा में सत्ता में वापसी के बाद, बीजेपी को उम्मीद है कि इसका महाराष्ट्र में भी असर होगा, जहां चार महीने पहले 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें जीतने के बाद से एमवीए उत्साहित दिख रहा है। कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर जटिल बातचीत के बीच बीजेपी को दूसरी हवा मिलेगी। जब हरियाणा में रुझानों से संकेत मिला कि बीजेपी सत्ता में लौट रही है, तो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों के अटूट विश्वास की पुष्टि करता है। अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत है।

पूर्व सांसद नवनीत राणा को मिली गैंगरेप की धमकी

पत्र में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा भी शामिल था और प्रेषक का फोन नंबर भी था। उन्होंने अपने पत्र में राणा के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उनके पति रवि राणा के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणी की।

महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व बीजेपी सांसद नवनीत राणा को एक पत्र मिला है जिसमें उन्हें सामूहिक बलात्कार की धमकी दी गई है। भेजने वाले ने खुद को आमिर बताया और 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। पत्र में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा भी शामिल था और प्रेषक का फोन नंबर भी था। उन्होंने अपने पत्र में राणा के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उनके पति रवि राणा के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणी की। सूत्रों के मुताबिक, पति रवि राणा के निजी सहायक विनोद गुहे ने राजापेठ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

इससे पहले अमरावती जिले के बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा ने पत्नी नवनीत राणा को लेकर बड़ा दावा किया है। रवि राणा ने कहा कि नवनीत राणा महाराष्ट्र

विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता का आश्वासन दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए, राणा ने कहा कि उनकी पत्नी, अमरावती से पूर्व लोकसभा सांसद, राज्य चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की पक्ष में प्रचार करेंगी। महाराष्ट्र में चुनाव अगले महीने होने की संभावना है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है।

रवि राणा ने कहा कि मुझे लगता है कि नवनीत राणा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चन्द्रशेखर बावनकुले और उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस तथा पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने लगातार कहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, जो मुझे लगता है कि उनके लिए उचित है। नवनीत राणा 2024 के लोकसभा चुनाव में अमरावती (एससी) सीट से कांग्रेस के बलवंत वानखड़े से हार गईं थीं। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सीट जीती थी और 2024 में भाजपा में शामिल हो गईं।

ASEAN देशों के लिए बताया भारत का सुपर प्लान

10 देशों के साथ पीएम मोदी ने चीन को घेरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो बयान दिया है उससे साफ है कि भारत अपनी प्राथमिकताओं को साफ करके चल रहा है। पूरी स्पष्टता के साथ भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान के 10 सदस्य देशों की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। भले ही वो छोटे से छोटा देश हो और भले ही उसकी अर्थव्यवस्था कैसी हो। भारत को उससे फायदा मिले या न मिले। लेकिन भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अपने तमाम मित्र देशों के साथ अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहता है। यही वजह है कि भारत उन देशों की सुरक्षा करने को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताता है और उन देशों को मदद भी दे रहा है जिनको किसी तरह का खतरा है।

आसियान देशों को कभी भी हथियार देने से भारत पीछे नहीं हटता है। आसियान के दस देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, थाइलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यामांर और कंबोडिया शामिल है। यही वजह है कि इनमें कई आयिसान देशों को लगातार चीन उनके क्षेत्र में घेरने की कोशिश कर रहा है तो भारत उन्हें हथियार देकर मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र हैं। हम शांति प्रिय देश हैं। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी

भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है।

भारत-आसियान मैत्री, समन्वय वार्ता और सहयोग ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण है जब विश्व के कई हिस्से संघर्ष और तनाव का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और आसियान देश पड़ोसी हैं और वैश्विक दक्षिण में साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि हम शांतिप्रेमी देश हैं और एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं तथा क्षेत्र के युवाओं के उज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने कहा कि आसियान की केंद्रीयता को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2019 में हिंद-प्रशांत महासागर पहल शुरू की थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए समुद्री अभ्यास शुरू किए गए उन्होंने कहा कि पिछले दशक में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार दोगुना होकर अब 130 अरब डॉलर से अधिक हो गया है।

डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई योजना नहीं : कमला हैरिस

राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वह (ट्रंप) केवल अपने बारे में ही सोचते हैं और अमेरिकियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है।

अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वह (ट्रंप) केवल अपने बारे में ही सोचते हैं और अमेरिकियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। एरिजोना में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए हैरिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि ट्रंप ने पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले किसी भी तरह की बहस करने से आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया है।

उन्होंने इसे मतदाताओं के साथ 'नाइंसाफी' बताया। हैरिस ने कहा, ''मुझे भी लगता है कि यह उनका बहुत ही

कमजोर कदम है। लेकिन अगर वह बहस नहीं भी करते हैं, तो भी इस चुनाव में अंतर पहले से ही स्पष्ट नजर आ रहा है।'' हैरिस ने कहा कि देश के लोगों के लिए कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ट्रंप के पास इस बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, ''हम अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और अपने सैनिकों का सम्मान करेंगे। इनके अलावा ऐसे कई और मुद्दे हैं, जो आपके और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं... लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा कहते हुए नहीं सुनते हैं। हम उन्हें इन मुद्दों के बारे में बात करते हुए नहीं सुनते हैं।''

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, ''इन मुद्दों पर बात करने के बजाय ट्रंप के पास वही पुरानी घिसी-पिटी रणनीति है। उनके पास अमेरिकी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ अपने आप पर है। खैर, अब बदलाव का समय आ गया है।'' हैरिस ने कहा कि अमेरिका एक नये रास्ते पर अग्रसर है और वह नये आशावादी नेतृत्व को अपनाने के लिए तैयार है।

2047 में IT और संस्कृति का केंद्र बनेगा भारत- वित्तमंत्री सीतारमण

1000 साल से भारत ने दर्शन, राजनीति, विज्ञान और कला का एक सांस्कृतिक क्षेत्र बनाया है। यह विजय के जरिए से नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक भव्यता के जरिए से सीमाओं के पार फैला है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करने पर 2047 तक भारत में विकसित देशों के समान सभी मुख्य विशेषताएं मौजूद हो जाएगी। उन्होंने यह बात कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कही है। मंत्री सीतारमण ने कहा कि यदि हम उपमहाद्वीप के सभ्यतागत इतिहास को देखें तो भारतीय युग कोई नई घटना नहीं है। 1000 साल से भारत ने दर्शन, राजनीति, विज्ञान और कला का एक सांस्कृतिक क्षेत्र बनाया है। यह विजय के जरिए से नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक भव्यता के जरिए से सीमाओं के पार फैला है।

पूरी दुनिया में आएगी समृद्धि

उन्होंने कहा कि भारत 2047 में विचारों, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के जीवंत आदान-प्रदान का केंद्र बनेगा, जिससे न केवल भारतीयों बल्कि पूरी दुनिया में समृद्धि आएगी। उन्होंने भारत के हाल के आर्थिक प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला, जिसमें भारत का 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और उच्च विकास दर बनाए रखना शामिल है। सीतारमण ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को अर्थशास्त्र और वित्त

के नीति विशेषज्ञों के लिए एक अहम मंच बताया और कहा कि नीति निर्माण में मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञों की सोच की जरुरत है।

भारत की युवा आबादी को भी बहुत अहम बताया

वित्तमंत्री सीतारमण ने भारत की युवा आबादी को भी बहुत अहम बताया, जिसका उत्पादन, बचत और निवेश में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि भारत को यह तय करना चाहिए कि युवा सुसज्जित, भावनात्मक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, जो कि एक मुख्य नीतिगत प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें कहा कि यह प्रणाली संकट प्रबंधन, विनियामक और शासन मानकों के मामले में विकसित वित्तीय बाजारों के बराबर है।

अनुसंधान के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित : सीतारमण ने कहा कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, बेहतर प्रावधान और बढ़ती लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 के बजट में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और शिक्षा जगत, निजी क्षेत्र और सरकारी निकायों के बीच सहयोग से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान कोष की स्थापना की गई है।

2034 तक देश में बढ़ेगी 75 हजार मेडिकल सीट

टारगेट के साथ काम कर रही केन्द्र सरकार : शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अगले 10 वर्षों में देशभर में और 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने की योजना बना रहा है। शाह ने अहमदाबाद शहर के पास अडालज गांव में एक न्यास द्वारा संचालित अस्पताल 'हीरामणि आरोग्यधाम' का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। जानिए उन्होंने क्या कहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले स्वच्छता अभियान शुरू किया, जो कई बीमारियों को खत्म करने के लिए एक सफाई अभियान था। फिर उन्होंने लोगों को कई अन्य बीमारियों से बचाने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और प्रत्येक घर में शौचालय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उसके बाद उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया और 5 लाख रु

तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए मोदी ने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करने के साथ-साथ देश भर में नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। शाह ने कहा, ''प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सभी 14 विभागों वाला एक अस्पताल होता है।

अब, हमने अगले 10 वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीट जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सस्ती जेनेरिक दवाइयां बेचने वाले सरकारी दवा दुकानों का जाल बनाना भी केंद्र के समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 140 करोड़ नागरिकों के लाभ के लिए 37 अलग-अलग योजनाएं शुरू की हैं और उन्हें लागू किया है। शाह गुजरात के दो-दिवसीय दौरे पर हैं।

बड़ा फैसला : गरीबों को वर्ष 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने पर मुहर लगा दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। जिसके चलते अब देश की गरीब जनता को अगले कुछ सालों तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने बुधवार (9 अक्टूबर 2024) को कई योजनाओं को हरी झंडी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने पर मुहर लगा दी।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीएस, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना के लिए केंद्र ने 17,082

करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पौष्टिक तत्वों से भरपूर यानी फोर्टिफाइड चावल लोगों में खून की कमी (एनीमिया) के समाधान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए अहम माना जाता है। चावल को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने की प्रक्रिया में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों (लौह, फोलिक एसिड, विटामिन बी12) से भरपूर 'फोर्टिफाइड' चावल कर्नेल (एफआरके) को नियमित चावल (कस्टम मिल्ड चावल) में मिलाया जाता है।

क्या है सरकार की पहल?

आधिकारिक बयान के अनुसार, "चावल को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने की पहल केंद्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में जारी रहेगी। इसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण पीएमजीकेएवाई (खाद्य सब्सिडी) के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत संस्थागत तंत्र उपलब्ध होगा।" सरकार ने कहा है कि "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), अन्य कल्याणकारी योजनाओं, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), पीएम पोषण (पूर्ववर्ती एमडीएम) के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति" की पहल की गई है। अप्रैल, 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने मार्च, 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चावल पौष्टीकरण पहल को लागू करने का निर्णय लिया था।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा

समस्या को सुलझाने से 20% आय बढ़ना संभव

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि किसानों की छोटी-छोटी समस्याओं को सुलझाने से उनकी आय में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। मंत्री चौहान ने 24 सितंबर को शुरू हुई अपनी 'सीधा संवाद' पहल के तहत भारतीय किसान संघ (स्वतंत्र) के सदस्यों से मुलाकात की हैं। उन्होंने इस दौरान कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की हैं।

किसानों की सेवा को भगवान की पूजा बताते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये समस्याएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका समाधान करने से किसानों की आय में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कारखाने के दूषित पानी और जले हुए ट्रांसफार्मर को कम समय में बदलने पर चर्चा की है। चर्चा के दौरान

फसल की लागत कम करने, उचित मूल्य सुनिश्चित करने और जलभराव को रोकने पर भी बात हुई है।

कृषक समुदायों के बीच सीधा संवाद कायम

उन्होंने कहा कि, इसके अलावा, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग, स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और पीएम फसल बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुंच पर चर्चा की गई। चौहान ने विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए हर मंगलवार को किसानों और कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलने की प्रतिबद्धता जताई है। संवाद पहल का उद्देश्य समस्या समाधान में तेजी लाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय और कृषक समुदायों के बीच सीधा संवाद कायम करना है।

सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र तो सबसे गरीब राज्य बिहार

दस सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आए बाहर

भारत में गरीबी एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जो ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के संयोजन से प्रभावित है। वर्ष 2023-24 में भारतीय राज्यों की जीडीपी के अनुसार, महाराष्ट्र सबसे धनी राज्य और बिहार सबसे गरीब राज्य माना गया है।

हाल में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार के दस साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उनके जीवन में सुधार आया है, मगर गरीबी और इसके कारणों को विस्तार से समझने की जरूरत है। उसके बाद ही गरीबी हटाने के उपायों को कारगर बनाया जा सकता है। भारत में गरीबी एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जो ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के संयोजन से प्रभावित है। वर्ष 2023-24 में भारतीय राज्यों की जीडीपी के अनुसार, महाराष्ट्र सबसे धनी राज्य और बिहार सबसे गरीब राज्य माना गया है। नीति आयोग की नवीनतम रपट के अनुसार, पिछले नौ वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जो कि लगभग 13.88 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का दावा करती है। रपट पिछले नौ वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89 फीसद की गिरावट की ओर इशारा करती है, क्योंकि इस स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या 2013-14 में 29.17 फीसद थी और 2022-23 में 11.28 फीसद (लगभग 15.5 करोड़ भारतीय) थी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) गरीबी के स्तर और तीव्रता को मापने के लिए तीन व्यापक आयामों- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का उपयोग करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सौ से अधिक विकासशील देशों में गरीबी के स्तर को निर्धारित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया है।

भारत ने अपने राष्ट्रीय एमपीआइ में स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आयामों के तहत दो नए मानक- मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते जोड़े हैं। भारत में हर घर को इन बारह मानदंडों के आधार पर अंक दिया जाता है। अगर किसी घर का अभाव अंक 33 फीसद से अधिक है, तो उसे बहुआयामी गरीब के रूप में पहचाना जाता है। नीति आयोग की रपट बताती है कि भारत अपने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की संभावना रखता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक बहुआयामी गरीबी को आधा करना है। रपट इस बात पर जोर देती है कि पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री जन-धन योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

वहीं फरवरी, 2024 में जारी भारतीय स्टेट बैंक के शोध के अनुसार, देश में गरीबी दर 2022-23 में 4.5-5 फीसद तक गिर गई। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर एसबीआइ शोध ने इस गिरावट का श्रेय पिरामिड के निचले हिस्से के लिए शुरू किए गए सरकारी कार्यक्रमों को दिया है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण गरीबी 2011-12 में 25.7 फीसद से घटकर 7.2 फीसद हो गई और शहरी गरीबी एक दशक पहले से 4.6 फीसद कम हो गई है। एसबीआइ शोधकर्ताओं के अनुसार, नई गरीबी रेखा क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,622 रुपए और 1,929 रुपए थी। इन आंकड़ों की गणना सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिन्होंने 2011-12 में गरीबी रेखा निर्धारित की थी। वर्ष 2023 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रपट के अनुसार, दुनिया के कुल गरीबों में एक तिहाई से अधिक दक्षिण एशिया में रहते हैं, जो लगभग 38.9 करोड़ हैं। भारत अत्यधिक गरीबी में लगभग 70 फीसद की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2.15 डालर की दर से अत्यधिक गरीबी तय की जाती है, जबकि 3.65 डालर निम्न-मध्यम आय श्रेणी में आता है तथा 6.85 डालर उच्च-मध्यम आय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 3.65 डालर निर्धारित गरीबी रेखा पर विचार करते हुए भारत का योगदान वैश्विक गरीबी दर में मामूली वृद्धि के साथ 40 फीसद के बराबर है, जो 23.6 फीसद से बढ़कर 24.1 फीसद हो गई है।

प्रशासनिक कामकाज में हर स्तर पर होता महिलाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, यह परिदृश्य तब और भी गंभीर हो जाता है जब हम एक देश के रूप में सार्वजनिक कार्यालयों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से निर्वाचित निकायों में पर्याप्त महिला प्रतिनिधियों समेत सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रगतिशील लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि पंचायत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सरकारी अथॉरिटी के लापरवाह रवैये से हटा दिया जाता है। यह प्रशासनिक कामकाज के सभी स्तरों पर व्याप्त पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार के प्रणालीगत स्वरूप को दर्शाता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रशासनिक कामकाज के सभी स्तरों पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का एक व्यवस्थित पैटर्न है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, यह परिदृश्य तब और भी गंभीर हो जाता है जब हम एक देश के रूप में सार्वजनिक कार्यालयों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से निर्वाचित निकायों में पर्याप्त महिला प्रतिनिधियों समेत सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रगतिशील लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नासिक में एक महिला सरपंच की अयोग्यता को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने के मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब यह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से जुड़ा हो। पीठ ने कहा, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये महिलाएं जो ऐसे सार्वजनिक पदों पर कब्जा करने में सफल होती हैं, वे काफी संघर्ष के बाद ही ऐसा करती हैं।

क्या है मामला

फरवरी, 2021 में सरपंच के रूप में निर्वाचित अपीलकर्ता मनीषा रवींद्र पानपाटिल को जिला कलेक्टर ने इस आरोप पर अयोग्य घोषित कर दिया था कि वह अपनी सास के साथ सरकारी जमीन पर बने घर में रह रही थी। मंडलायुक्त ने आदेश को बरकरार रखा और हाईकोर्ट ने भी उसकी याचिका खारिज कर दी। महिला ने उस विशेष आवास में रहने से इन्कार किया और दावा किया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ किराये के मकान में अलग रहती है। उसने कहा कि संबंधित आवास इतनी जर्जर स्थिति में था कि उसमें रहना संभव नहीं था। पीठ ने उसे हटाए जाने को अत्यधिक असंगत मानते हुए कहा कि तथ्य-खोज अभ्यास करने की दिशा में कोई प्रयास किए बिना ही आदेश को लापरवाही से पारित किया गया।

सरकारी महकमे ने निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने में लापरवाही बरती

पीठ ने कहा, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि निजी व्यक्तियों (प्रतिवादियों) ने भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया होगा लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि सरकारी अथॉरिटी ने एक निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने में लापरवाही बरती। यह तब और भी अधिक चिंताजनक हो जाता है जब संबंधित प्रतिनिधि एक महिला है और आरक्षण कोटे में चुनी गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रशासनिक कामकाज के सभी स्तरों पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का एक व्यवस्थित पैटर्न व्याप्त है।

गांव वाले इसे स्वीकार नहीं कर पाए कि महिला सरपंच बनी : पीठ ने कहा कि यह सटीक मामला है, जहां गांव वाले यह स्वीकार नहीं कर पाए कि अपीलकर्ता, एक महिला होने के बावजूद, सरपंच बन गई।

मोदी सरकार की कृषि सुधार योजनाओं से उत्पादन और किसानों की आय में हो रही है बढ़ोतरी : भागीरथ चौधरी

कृषि सुधार के लिए केंद्र सरकार ने उठाए क्रांतिकारी कदमः कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि हमारे देश की कृषि क्षेत्र की प्रगति में किसानों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और यह हमारे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और समृद्धि का आधार है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शनिवार को पूसा परिसर नई दिल्ली में आयोजित 'राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन- रबी अभियान 2024' के शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित किया। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, सहित विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रीगण एवं कृषि विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कृषि सुधार के लिए केंद्र सरकार ने उठाए क्रांतिकारी कदम

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि हमारे देश की कृषि क्षेत्र की प्रगति में किसानों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और यह हमारे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और समृद्धि का आधार है। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें तकनीकी, वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि सुधार की दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं, इससे उत्पादन और किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रबी की फसलें भारतीय कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह हमारे खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करती हैं।

रबी फसलों में एमएसपी वृद्धि का निर्णय ऐतिहासिक

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारतीय किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हो। रबी सीजन के इस अवसर पर हमें अपने किसानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पूरी मेहनत और लगन से काम करना होगा तथा सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किसान हित में अपना एजेंडा सुनिश्चित करते हुए हाल ही में 6 रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया जोकि निश्चित रूप से कृषि एवं किसान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

श्रीलंका नेवी ने अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 17 भारतीय मछुआरों को पकड़ा...

अपने जलक्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर उनकी नौकाएं जब्त कर लीं। अब इन 17 मछुआरों को मिला कर इस साल द्वीप राष्ट्र में ऐसी घटनाओं में पकड़े गए भारतीय नागरिकों की संख्या 413 हो गई है। श्रीलंका की नौसेना ने अपने जलक्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में 17 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर उनकी नौकाएं जब्त कर लीं। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि इन 17 मछुआरों को मिला कर इस साल द्वीप राष्ट्र में ऐसी घटनाओं में पकड़े गए भारतीय नागरिकों की संख्या 413 हो गई है। श्रीलंकाई नौसेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और मन्नार के उत्तर में उनकी दो नौकाएं जब्त की गईं।

विज्ञप्ति के अनुसार, नौसेना ने भारतीय मछुआरों को पकड़ने के लिए ''विशेष अभियान'' चलाया। इसमें कहा गया है कि पकड़े गए 17 मछुआरों को तलाईमन्नार पियर ले जाया गया और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें मन्नार मत्स्य निरीक्षक को सौंप दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि श्रीलंकाई नौसेना ने ''2024 में अब तक द्वीप के जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाली 55 भारतीय नौकाओं को और 413 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है और उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंप दिया है।''

मछुआरों का मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा है। श्रीलंकाई जलक्षेत्र में कथित रूप से अवैध तरीके से प्रवेश करने के मामलों में श्रीलंकाई नौसेना के कर्मी पाक जलडमरूमध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी करते हैं और उनकी नौकाओं को जब्त कर लेते हैं। पाक जलडमरूमध्य, तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली पानी की एक संकरी पट्टी है, जो दोनों देशों के मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का एक समृद्ध क्षेत्र है। दोनों देशों के मछुआरों को अनजाने में एक-दूसरे के जलक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अक्सर गिरफ्तार किया जाता है।

ब्रिटेन का आखिरी कोयला बिजली संयंत्र बंद, 142 साल पुरानी कोयला बिजली खत्म होगी

ब्रिटेन सरकार ने 2030 तक देश के लिए समूची ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करने के प्रयासों में एक मील के पत्थर के रूप में कोयला आधारित बिजली संयंत्र के बंद होने की सराहना की।

ब्रिटेन का आखिरी कोयला आधारित बिजली संयंत्र सोमवार को बंद हो जाएगा, जिससे देश में औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाली कोयला विद्युत की 142 साल पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

मध्य इंग्लैंड स्थित 'रैटक्लिफ-ऑन-सोर स्टेशन' अपनी अंतिम पाली के साथ आधी रात से हमेशा के लिए विराम ले लेगा। ब्रिटेन सरकार ने 2030 तक देश के लिए समूची ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करने के प्रयासों में एक मील के पत्थर के रूप में कोयला आधारित बिजली संयंत्र के बंद होने की सराहना की। ऊर्जा मंत्री माइकल शैंक्स ने कहा, ''संयंत्र का बंद होना एक युग के अंत का प्रतीक है और कोयला श्रमिक 140 वर्षों से अधिक समय से हमारे देश को बिजली प्रदान करने वाले अपने काम पर

गर्व कर सकते हैं। एक देश के रूप में हम पीढ़ियों के प्रति ऋणी हैं।" उन्होंने कहा, ''कोयले का युग शायद ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारे देश के लिए अच्छी ऊर्जा वाली नौकरियों का एक नया युग अभी शुरू हो रहा है।

उप्र की मजबूत कानून व्यवस्था और जातिवाद की जहरीली राजनीति...

योगीराज में प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने लिए साढ़े सात वर्षो में 49 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त 872 नशा व हथियार तस्करी अपराधी और 379 साइबर अपराधियां को गिरफ्तार किया है।

लोकसभा चुनावों में पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़कर 37 हो जाने से समाजवादी पार्टी विशेष उत्साह में है और जहाँ जहाँ भी उसके सांसद जीते हैं वहाँ वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता न केवल अराजकता का वातावरण बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं वरन जातिवादी जहर घोलने का प्रयास भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपराध और अपराध जगत पर जीरो टालरेंस की नीति पर चल रही है जिसमें कुख्यात माफियाओं व अपराधियो के एनकाउंटर हो रहे हैं तथा बुलडोज़र भी चलाये जा रहे हैं, कई जगह अपराधी स्वयं ही आत्समर्पण भी कर रहे हैं या फिर अपना काम धंधा बदल रहे हैं।

प्रदेश का जन सामान्य योगी सरकार की बुलडोज़र नीति से प्रसन्न है जबकि विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा था कि बुलडोज़र से लोगों को डराया जा रहा है या अल्पसंख्यको को सताया जा रहा है आदि-आदि। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर अंतरिम रोक लगाई तो पूरा विपक्ष खुशियाँ मनाने लगा जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को अपने आदेश से अलग रखा था। योगी राज्य में बुलडोज़र केवल अतिक्रमण पर ही चलता है अतः प्रशासन को अपना काम करने में कोई समस्या नहीं आई।

आश्चर्यजनक रूप से समाजवादी नेता अपनी जातिवाद की राजनीति को और पैना करने के लिए अपराधियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। वहीं विगत दिनों हुई कुछ आपराधिक घटनाओं में शामिल लोग समाजवादी पार्टी से सम्बंधित रहे हैं संभवतः यही कारण है कि समाजवादी नेता अखिलेश यादव सहित अन्य सभी जातिवादी नेता जातिवाद के जहर को और तीखा कर रहे हैं। अयोध्या से लेकर कनौज तक दुष्कर्म की जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं उसमें सपा कनेक्शन मिला, प्रयागराज में अवैध मदरसे में चल रहा जाली नोट का व्यापार व फिर कौशाम्बी में जाली नोट खपाने वाले सपा के दो नेता अपने दस सहयोगियों के साथ पकड़े गए स्वाभाविक रूप से आपराधिक घटनाओं में लिप्त पार्टी को बैकफुट पर जाने से बचाने के लिए ही अपराध की वीभत्सता तथा गम्भिरता की जगह अपराधी की जाति बीच में लाई जा रही है।

अगस्त माह के अंत में सुल्तानपुर में डकैती डालने आये गिरोह के सदस्यों का एनकाउंटर हुआ जिसमें से एक मंगेश यादव के नाम पर समाजवादी नेता यादव समाज की सहानुभूति बटोरने के लिए उसके घर पहुंच गये और उसका महिमा मंडन करते हुए कहा कि यह एनकाउंटर नहीं एक हत्या है और अब सपा इस मामले को आगामी विधानसभा सत्र में भी जोर शोर से उठाने जा रही है। समाजवादी नेता आजकल जातिगत आधार पर ही अपराध और अपराधियों का संरक्षण व महिमामंडन कर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में आज सभी दल अपराधी की जाति देखकर उस पर होने वाली कार्यवाही का तीखा विरोध कर रहे हैं जबकि प्रदेश में 2012 से 2017 तक सपा सरकार के शासन काल में पुलिस मुठभेड़ में 34 अपराधी मारे गये थे तथापि उनके शासनकाल में अपराध और अपराधियों का जोरदार बोलबाला था। एक समय था कि कोई सपने में भी नहीं सोच पाता था कि प्रदेश को कभी अतीक जैसे माफियाओं से मुक्ति मिलेगी या फिर बड़े सफेदपोश लोग जेल जाएंगे।

पिछली सरकारों के कई एनकाउंटर में तो मजिस्ट्रेट जांच तक नहीं ती थी। जबकि योगी सरकार में सभी एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच हो रही है यहां तक कि कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में हुई स्वाभाविक मौत की भी जांच हुई। योगीराज में प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने लिए साढ़े सात वर्षो में 49 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त 872 नशा व हथियार तस्करी अपराधी और 379 साइबर अपराधियां को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3,970 संगठित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश सरकार अवैध नशे के खिलाफ भी व्यापक अभियान चला रही हे जिसमें अभियुक्तों से सर्वाधिक गांजा बरामद हुआ है व अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद हो रहे हैं ।

समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने एसटीएफ को भी नहीं छोड़ा ओर उसमें शामिल अधिकारियों की जाति को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उकेर दिया ओर बताया कि कौन सा अधिकारी किस जाति का है। जब जातिवाद की राजनीति बहुत उग्र होने लग गई तब आंकड़ों को देखने से स्पष्ट हुआ कि विगत 7 साल में 207अपराधी एनकाउटर में मारे गये जिसमें- 67 मुसिलम, 20 ब्राहमण, 18 ठाकुर, 17 जाट और गुर्जर 16 यादव, 14 दलित, तीन ट्राइबल, दो सिक्ख, 8 ओबीसी और 42 दूसरी जातियों के थे।

भगवान शिव स्त्रोत का पाठ करने से मिलेगी सभी कार्यों में सफलता...

वैसे तो हर दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाती है। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सच्चे मन से शिव मृत्युञ्जय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। हर साल आश्विन माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाती है। साथ ही सुख-समृद्धि की भगवान शिव से कामना की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत होता है और व्यक्ति पर मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा होती है। वैसे तो हर दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाती है। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सच्चे मन से शिव मृत्युञ्जय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है।

॥ शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् ॥

रत्नसानुशरासनं रजताद्रिश्रृंगनिकेतनं।
शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्।।
क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवंदितं।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥
पंचपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं।
भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्।।
भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥
मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं
पंकजासनपद्मलोचनपूजितांघ्रिसरोरुहम्।।
देवसिद्धतरंगिणी करसिक्तशीतजटाधरं।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥
कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं।
नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्।।
अंधकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥
यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजंगविभूषणं।
शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्।।
क्ष्वेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥
भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं।
दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्।।
भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसंघनिबर्हणं।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥
भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं।
सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूपमम्।।
भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिं।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥
विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं।
संहरन्तमथ प्रपंचमशेषलोकनिवासिनम्।
क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं।
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥
रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥
कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥
नीलकण्ठं विरुपाक्षं निर्मलं निरूपद्रवम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥
वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥
देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषभध्वजम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥
अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥
आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥
स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥
॥ इति श्रीपद्मपुराणान्तर्गत उत्तरखण्डे
श्रीमृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

बांसुरी में बसते हैं भगवान श्रीकृष्ण के प्राण, भगवान शिव से संबंध...

बांसुरी के बारे में यह कहना या बताना संभव नहीं है कि यह सर्वप्रथम कब से आया पौराणिक कथाओं की माने तो श्री कृष्ण के द्वारा ही उसका जन्म हुआ, बांसुरी स्वर की निष्पत्ति जब करती है तो यह सम्मोहन और जीवन ऊर्जा से भरी हुई है। ताल पर नाचे राधा बावरिया बांसुरी बजाए मोरा सांवरिया, अक्सर जब हम श्रीकृष्ण के रास की बात करते हैं, तो यह संभव ही नहीं है कि हम श्री कृष्ण को बिना बांसुरी के देख पाए। कहा जाता है की बांसुरी और श्री कृष्ण एक दूसरे के साथ वैसे ही है, जैसे कि राधा -कृष्ण। आज भी श्री कृष्ण का रास बिना बांसुरी के संभव नहीं है। आज हम बात करेंगे संगीत के सबसे प्राचीन वाद्य की।

यह सोचना और जानना उतना ही अद्भुत और अलौकिक है, की एक संगीत का ऐसा वाद्य यंत्र जो सिर्फ एक बांस से निर्मित है और इसमें पूर्ण संगीत समाया हुआ है, बांसुरी के बारे में यह कहना या बताना संभव नहीं है कि यह सर्वप्रथम कब से आया पौराणिक कथाओं की माने तो श्री कृष्ण के द्वारा ही उसका जन्म हुआ, बांसुरी स्वर की निष्पत्ति जब करती है तो यह सम्मोहन और जीवन ऊर्जा से भरी हुई है। बांसुरी के बारे में विस्तार से जानने के लिए विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित अजय प्रसन्ना से बात हुई।

'बांसुरी' श्री कृष्ण का प्रिय संगीत वाद्य है, कहा जाता है के श्री कृष्ण के प्राण बांसुरी में बसते थे। यह अन्य वाद्य से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसकी बनावट बांस की है और इसको बजाने से पहले किसी भी तरह से ट्यून नहीं किया जा सकता, इसको पूर्णता संपूर्ण ज्ञान के साथ ही बजाया जा सकता है। कुछ कथाओं की मानें तो बांसुरी की परिकल्पना भी शिव ने ही की थी और यह संभव भी है क्यूंकि शंकर नृत्य ,और नाद के देव है।शिव जी ने उस दधीचि की हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेट स्वरूप वह बंसी प्रदान की। उन्हें आशीर्वाद दिया तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं।

जब उनका जन्म हुआ तभी से वह बांसुरी सुनते आ रहे थे क्योंकि उनके पिताजी एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बांसुरी के लिए समर्पित किया और 3 साल की उम्र से ही अजय प्रसन्ना की यात्रा शुरू हुई। प्रथम समय में जब गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उनकी शिक्षा शुरू की गई, तब उनके पिताजी पंडित भोलानाथ प्रसन्ना ने अपने हाथों से बांसुरी बनाकर पंडित अजय प्रसन्ना की शिक्षा शुरू की। नाट्यशास्त्र के अनुसार यह 2000 साल से भी पुराना शास्त्र है, जिसमें नृत्य, गीत, वादन कहा जा सकता है। सभी मंची कलाओं का शास्त्र है इसलिए इसे पंचम वेद भी कहते हैं।

सूर्य देव के इन 108 नामों का करें जाप

मिलेगी जीवन व करियर में मनचाही सफलता...

हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित होता है। वहीं रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए रोजाना सुबह जल्दी स्नान आदि कर विधिविधान से सूर्य देव की पूजा अर्चना जल अर्पित करना चाहिए।

हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित होता है। वहीं रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए रोजाना सुबह जल्दी स्नान आदि कर विधिविधान से सूर्य देव की पूजा अर्चना जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने और अर्घ्य देने से जातक को करियर और कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए रोजाना सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा के दौरान उनके 108 नामों का जप करना चाहिए। इससे जातक के बिगड़े काम पूरे होते हैं और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है।

सूर्यदेव 108 नाम

ॐ अरुणाय नमः
ॐ शरण्याय नमः
ॐ करुणारससिन्धवे नमः
ॐ असमानबलाय नमः
ॐ आर्तरक्षकाय नमः
ॐ आदित्याय नमः
ॐ आदिभूताय नमः
ॐ अखिलागमवेदिने नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ अखिलज्ञाय नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ इनाय नमः
ॐ विश्वरूपाय नमः
ॐ इज्याय नमः
ॐ इन्द्राय नमः
ॐ भानवे नमः
ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः
ॐ वन्दनीयाय नमः
ॐ ईशाय नमः
ॐ सुप्रसन्नाय नमः
ॐ सुशीलाय नमः
ॐ सुवर्चसे नमः
ॐ वसुप्रदाय नमः
ॐ वसवे नमः
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ उज्ज्वल नमः
ॐ उग्ररूपाय नमः
ॐ ऊर्ध्वगाय नमः
ॐ विवस्वते नमः
ॐ उद्यत्किरणजालाय नमः
ॐ हृषीकेशाय नमः
ॐ ऊर्जस्वलाय नमः
ॐ वीराय नमः
ॐ निर्जराय नमः
ॐ जयाय नमः
ॐ ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः
ॐ ऋषिवन्द्याय नमः
ॐ रुग्घन्त्रे नमः
ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः
ॐ ऋजुस्वभावचित्ताय नमः
ॐ नित्यस्तुत्याय नमः
ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः
ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः
ॐ ऋक्षाधिनाथमित्राय नमः
ॐ पुष्कराक्षाय नमः
ॐ लुप्तदन्ताय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ कान्तिदाय नमः
ॐ घनाय नमः
ॐ कनत्कनकभूषाय नमः
ॐ खद्योताय नमः
ॐ लूनिताखिलदैत्याय नमः
ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः
ॐ अपवर्गप्रदाय नमः
ॐ आर्तशरण्याय नमः
ॐ एकाकिने नमः
ॐ भगवते नमः
ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः
ॐ गुणात्मने नमः
ॐ घृणिभृते नमः
ॐ बृहते नमः
ॐ ब्रह्मणे नमः
ॐ ऐश्वर्यदाय नमः
ॐ शर्वाय नमः
ॐ हरिदश्वाय नमः
ॐ शौरये नमः
ॐ दशदिक्संप्रकाशाय नमः
ॐ भक्तवश्याय नमः
ॐ ओजस्कराय नमः
ॐ जयिने नमः
ॐ जगदानन्दहेतवे नमः
ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः
ॐ उच्चस्थान समारूढरथस्थाय नमः
ॐ असुरारये नमः
ॐ कमनीयकराय नमः
ॐ अब्जवल्लभाय नमः
ॐ अन्तर्बहिः प्रकाशाय नमः
ॐ अचिन्त्याय नमः
ॐ आत्मरूपिणे नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ अमरेशाय नमः
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः
ॐ अहस्कराय नमः
ॐ रवये नमः
ॐ हरये नमः
ॐ परमात्मने नमः
ॐ तरुणाय नमः
ॐ वरेण्याय नमः
ॐ ग्रहाणांपतये नमः
ॐ भास्कराय नमः
ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः
ॐ सौख्यप्रदाय नमः
ॐ सकलजगतांपतये नमः
ॐ सूर्याय नमः
ॐ कवये नमः
ॐ नारायणाय नमः
ॐ परेशाय नमः
ॐ तेजोरूपाय नमः
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
ॐ सम्पत्कराय नमः
ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः
ॐ अं सुप्रसन्नाय नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ श्रेयसे नमः
ॐ सौख्यदायिने नमः
ॐ दीप्तमूर्तये नमः
ॐ निखिलागमवेद्याय नमः
ॐ नित्यानन्दाय नमः

इम्यूनिटी को कमजोर बनाता है यह खाना

हर साल 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व भर में भुखमरी और पोषण की कमी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। फूड दिवस पर कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों को भुखमरी के खिलाफ आवाज उठा कर सचेत किया जाता है। साथ ही भुखमरी और पोषण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

16 अक्तूबर 1945 में फूल और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (फाओ) की स्थापना हुई थी। फाओ के स्थापना दिवस के मौके पर विश्व खाद्य दिवस मनाने का फैसला लिया गया। भोजन या खाद्य सामग्री शरीर को स्वस्थ रखने, ऊर्जावान देने के लिए बेहद आवश्यक है। ऐसे में स्वस्थ खानपान शरीर को अधिक मजबूती देता है। इसके अलावा रोगों के जोखिमों से बचाने के लिए इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी कुछ खाद्य पदार्थ विशेष भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, इम्युनिटी का बनना सतत प्रक्रिया है यानी कि इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता होती है। इसमें पौष्टिक आहार की विशेष भूमिका होती है। हालांकि कुछ खाद्य सामग्रियां ऐसी भी हैं जिनका सेवन इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर आहार विशेषज्ञ से जानिए कि आहार की किन चीजों से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है?

प्रतिरक्षा प्रणाली से लेकर संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तला भुना खाना काफी नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा तली चीजों में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडेक्ट्स (एजीई) की अधिकता होती है, ये यौगिक स्वाभाविक उच्च तापमान पर चीजों को तलने से उत्पन्न होते हैं। एक शोध में वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि जो लोग अक्सर फ्रेंच फ्राइज जैसी तली हुई चीजें खाते हैं उनमें अवसाद की समस्या होने का जोखिम अधिक हो सकता है।

अधिक मीठे का सेवन कई रोगों का कारक बन सकता है। ज्यादा मीठी चीजें, चीनी या मीठे पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और एडेड शुगर वाली चीजें शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इसके साथ ही ये प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बनाने का काम भी करता है।

सिर्फ कुत्तों के काटने से ही नहीं, इन कारणों से भी फैलता है रेबीज...

हर साल 28 सितंबर को दुनियाभर में रेबीज दिवस मनाया जाता है। ये दिन रेबीज को लेकर जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जो एक घातक बीमारी है। रेबीज एक ऐसा घातक वायरस है जो ज्यादातर केस में मौत का कारण बनता है।

आमतौर पर रेबीज को कुत्तों से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि आमतौर पर ये कुत्तों के काटने से फैलता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं रेबीज सिर्फ कुत्तों के काटने से ही नहीं फैलता, बल्कि कुछ और भी कारण हैं जिनके चलते रेबीज फैलता है। चलिए आपको विश्व रेबीज दिवस 2024 पर बताते हैं रेबीज फैलने के कारणों, इसके लक्षण और बचाव के बारे में।

रेबीज क्या है?

रेबीज फैलने के कारण, बचाव और लक्षण के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि रेबीज है क्या। रेबीज एक घातक वायरस है, जो संक्रमित कुत्तों या जानवरों की लार में मौजूद होता है और इन जानवरों के काटने से फैलता है। अगर किसी व्यक्ति में एक बार रेबीज के लक्षण दिखने लगते हैं तो ज्यादातर मामलों में ये मौत का कारण बन सकता है।

रेबीज के कारण

किसी संक्रमित जानवर के काटने या खरोंच के कारण फैलता है। इसके अलावा मनुष्य को रेबीज तब भी हो सकता है जब किसी संक्रमित जानवर की लार सीधे किसी व्यक्ति की त्वचा के संपर्क में आती है। कुत्तों के काटने के अलावा बिल्ली, बीवर, गाय, बकरी, चमगादड़, रैकून, लोमड़ी, बंदर और कोयोट में भी रेबीज पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में संक्रमित कुत्तों के काटने या खरोंच से रेबीज होता है। रेबीज से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पालतू जानवरों को टीका लगवाएं और आवारा कुत्तों से थोड़ी दूरी बनाए रखें।

रेबीज के लक्षण

रेबीज के लक्षण आमतौर पर जल्दी दिखाई नहीं देते। जब किसी व्यक्ति को कोई संक्रमित जानवर काटता है या वह रेबीज के संपर्क में आता है तो वायरस लक्षण को पैदा करने से पहले शरीर के जरिए दिमाग तक पहुंचता है, इसके बाद ही लक्षण दिखाई देते हैं। रेबीज किसी व्यक्ति के शरीर में 1 से 3 महीने तक निष्क्रिय रह सकता है। रेबीज के लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे पहला संकेत है बुखार का आना।

रेबीज से बचाव के उपाय

अगर किसी व्यक्ति को किसी कुत्ते, आवारा पशु या संक्रमित जानवर ने काट दिया है तो उसे तुरंत स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ घाव की जांच करेंगे और फिर ये निर्धारित करेंगे कि इलाज की जरूरत है या नहीं। इससे बचाव के लिए रेबीज का टेस्ट कराएं और साथ ही उस पशु का भी परीक्षण कराएं, जिसने व्यक्ति को काटा है। इसके अलावा रेबीज संक्रमित जानवर के काटने, उसके खरोंचने या उसके लार के सीधे त्वचा के संपर्क में आने पर तुरंत रेबीज वैक्सीन लगवाएं। जंगली जानवरों से दूर रहें, चमगादड़ों को अपने घर के आसपास ना आने दें और अपने पालतू जानवर को रेबीज का टीका लगवाएं। पालतू जानवर किसी रेबीज संक्रमित जानवर के संपर्क में ना आएं, ये सुनिश्चित करने के लिए अपने पालतू जानवर को घर के अंदर ही रखें और अपनी देख-रेख में ही बाहर लेकर जाएं।

पूर्व कप्तान रानी रामपाल का बयान, कहा-

बरसों से महिला हॉकी लीग का इंतजार था, कोच के रूप में जुड़ना भी गर्व की बात...

'पोस्टर गर्ल' रही पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने महिला लीग की शुरूआत को देश में खेल के लिये मील का पत्थर बताते हुए कहा कि उन्हें बरसों से इसका इंतजार था और अब खिलाड़ी के रूप में भले ही नहीं लेकिन कोच के तौर पर भी इससे जुड़कर वह गर्व महसूस कर रही हैं।लाइव खेल ऑनलाइन देखें

भारतीय महिला हॉकी की 'पोस्टर गर्ल' रही पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने महिला लीग की शुरूआत को देश में खेल के लिये मील का पत्थर बताते हुए कहा कि उन्हें बरसों से इसका इंतजार था और अब खिलाड़ी के रूप में भले ही नहीं लेकिन कोच के तौर पर भी इससे जुड़कर वह गर्व महसूस कर रही हैं।

टोक्यो ओलंपिक 2021 में ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम की कप्तान रही रानी देश में पहली बार शुरू हो रही हॉकी इंडिया महिला लीग में पंजाब और हरियाणा के सूरमा हॉकी क्लब की मेंटर और कोच होंगी। रानी ने यहां महिला लीग के लिये खिलाड़ियों की नीलामी से इतर से कहा ,'' हॉकी मेरा जुनून है। मैने जितने समय खेला, जुनून के साथ खेला। मेरे दिमाग में हमेशा से यह था कि भारतीय हॉकी से जुड़ने के लिये जो भी मौका मिलेगा, उसे मैं स्वीकार जरूर करूंगी।हॉकी मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी।''

भारत के लिये 212 मैचों में 134 गोल कर चुकी पद्मश्री से सम्मानित 30 वर्ष की इस खिलाड़ी ने कहा ,'' मैने राष्ट्रीय टीम में वापसी की बहुत कोशिश की लेकिन ओलंपिक से पहले हो नहीं पाया। इस महिला लीग के लिये हमने बहुत साल इंतजार किया है और जब यह शुरू हुई तो खिलाड़ी नहीं लेकिन कोचिंग स्टाफ के तौर पर जुड़कर भी बहुत अच्छा लग रहा है।''

यह पूछने पर कि क्या लीग में खेलने की इच्छा नहीं थी, रानी ने कहा कि कई बार कठिन फैसले लेने पड़ते हैं हालांकि उन्होंने खेल से संन्यास के बारे में कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा,'' मैं एक महिला खिलाड़ी हूं और मैने बहुत संघर्ष झेला है। एक खिलाड़ी हमेशा खिलाड़ी होता है। खेलने की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती। कई बार आपको कठिन फैसला लेना होता है और मैने कोचिंग स्टाफ के साथ जुड़ने का फैसला किया।''

उन्होंने कहा ,'' संन्यास के बारे में बोलना अभी मुश्किल है। अभी लीग में नयी चुनौती का सामना करूंगी और उसके बाद कोई अंतिम फैसला लूंगी।'' पेरिस ओलंपिक 2024 के लिये क्वालीफाई नहीं कर पाने को भारत में महिला हॉकी के लिये झटका बताते हुए पूर्व कप्तान ने कहा कि अतीत को भुलाकर अब 2026 एशियाई खेलों और 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक पर फोकस करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास हरेंद्र सिंह के रूप में एक सक्षम कोच है जो पोडियम फिनिश का सपना पूरा कर सकते हैं।

हरियाणा के शाहबाद की रहने वाली इस खिलाड़ी ने कहा ,'' तोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहना बहुत बड़ा पल था। इसके लिये बहुत साल लगे और खिलाड़ियों, महासंघ, कोचों ने बहुत मेहनत की थी। हमने 2024 में पेरिस के लिये क्वालीफाई नहीं किया जो करारा झटका था लेकिन खेल में हर दिन नयी सीख होती है। जीत और हार खेल का हिस्सा हैं।'' इस महान स्ट्राइकर ने कहा ,''कोई भी टीम हारना नहीं चाहती। हम अतीत को बदल नहीं सकते लेकिन अब 2028 के लिये देखना है। पहला लक्ष्य 2026 एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतकर ओलंपिक के लिये सीधे क्वालीफाई करना होना चाहिये। महिला लीग खिलाड़ियों का पूल तैयार करने में काफी मददगार हो सकती है।''

उन्होंने कहा,''हरेंद्र सर कोच के तौर पर लौटे हैं जिनके साथ मैंने काफी हॉकी खेली है। उनके साथ सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह हमारी संस्कृति और जानते हैं। हमारे कई खिलाड़ी ग्रामीण इलाकों से आते हैं और उनसे हिन्दी में बात करने पर समझ में आता है।'' उन्होंने कहा ,'' हरेंद्र सर हमेशा देश के लिये जीतने की सोचते हैं और वही भावना खिलाड़ियों में भी डालते हैं। खिलाड़ियों के दिल को छूने के लिये बहुत बड़ा माध्यम है और हमें यकीन है कि हरेंद्र सर के साथ 2028 में टीम अच्छा करेगी।''

रानी ने स्वीकार किया कि महिला लीग के पहले सत्र में नीलामी के लिये पर्स छोटा है लेकिन उम्मीद जताई कि आने वाले समय में अधिक फ्रेंचाइजी लीग से जुड़ेंगी और पैसा भी बढेगा। उन्होंने कहा ,''नीलामी के लिये पर्स कम जरूर है लेकिन कोई भी चीज शुरू करना कठिन होता है। हॉकी इंडिया के लिये भी यही है लेकिन लीग का प्रभाव अच्छा रहता है तो उम्मीद है कि और टीमें आगे आयेंगी और पर्स भी बढेगा।हमारे खिलाड़ी बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं तो आर्थिक तौर पर यह लीग बहुत मदद करेगी।''

एचआईएल महिला लीग के पहले सत्र में चार टीमें सूरमा हॉकी क्लब, बंगाल टाइगर्स, दिल्ली एसजी पाइपर्स और ओडिशा वारियर्स हैं। टीमों को नीलामी में दो करोड़ रूपये की सीमा दी गई है जबकि खिलाड़ियों को तीन बेसप्राइज दस लाख, पांच लाख और दो लाख रूपये में बांटा गया है।

उन्होंने कभी मेरे पिता को धन्यवाद नहीं दिया

बहन विनेश पर भड़कीं बबीता

अंतरराष्ट्रीय पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट ने अपनी चचेरी बहन विनेश फोगाट पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता महावीर फोगाट ने विनेश को बतौर कोच ट्रेनिंग दी, लेकिन उन्होंने कभी अपने चाचा का धन्यवाद नहीं दिया। बता दें कि, पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किग्रा कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से बढ़े वजन के कारण बाहर होना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और कांग्रेस में शामिल हो गईं।

2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली बबीता ने सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए विनेश द्वारा महावीर फोगाट की सराहना न करने पर अपनी निराशा व्यक्त की। विनेश के पिता के निधन के बाद महावीर ने उनके कोच की भूमिका निभाई थी। बबीता ने कहा- आपने देखा होगा कि जब मनु भाकर ओलंपिक पदक लेकर घर लौटीं तो उनके कोच उनके साथ थे। इसी तरह अमन सेहरावत पदक लेकर लौटे और उनके साथ उनके कोच भी थे। लेकिन जब विनेश लौटीं तो दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे। लोगों के लिए बेहतर होगा कि उन्हें (दीपेंद्र को) द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाए। मेरा मानना है कि अगर मेरे पिता एयरपोर्ट पर उनके साथ खड़े होते तो इस स्थिति को लेकर इतनी राजनीति नहीं होती।

विनेश के फाइनल से बाहर होने पर भावुक हो गए थे

महावीर : इस दौरान बबीता ने बताया कि जब विनेश को फाइनल से पहले अयोग्य करार दिया गया था, तब उनके पिता महावीर भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा- मैंने अपने पिता को सिर्फ तीन बार रोते देखा है। पहली बार तब जब मेरी और मेरी बहनों की शादी हुई थी। दूसरी बार जब मेरे चाचा का निधन हुआ था और तीसरी बार वह विनेश के ओलंपिक फाइनल से बाहर होने पर रोए थे।

बबीता ने कहा- इन बातों को समझने की जरूरत है। मैंने देखा है कि कैसे मेरे पिता ने कभी विनेश को उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। जब मेरे चाचा का निधन हुआ, तो विनेश ने अपने भाई और बहन के साथ कुश्ती छोड़ दी। मेरे पिता उनके घर गए, उनकी मां से बात की और उन्हें खेल में वापस ले आए। यहां तक कि जब वे सुबह 4 बजे प्रशिक्षण मैदान पर नहीं पहुंचते थे तो वह उनके घर जाते और उन्हें ले आते। जब कोई प्रशिक्षण में इतनी मेहनत करता है और उसे कभी धन्यवाद नहीं मिलता है, तो यह किसी भी कोच के लिए भावनात्मक रूप से समझ में आने वाली बात है।

38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से उत्तराखण्ड में होंगेः पुष्करसिंह

38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखण्ड में होंगे। 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में इसका पूरा कार्यक्रम जारी किया जायेगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम का आयोजन भी उत्तराखण्ड में किया जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पी.टी उषा से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि उत्तराखण्ड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष पी.टी उषा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखण्ड पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य में काफी इन्फ्रास्टक्चर बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भव्य तरीके से किया जायेगा। जिन राज्यों में पिछले राष्ट्रीय खेल हुए हैं, उनके अनुभवों के आधार पर भी राज्य में और अच्छे तरह से खेलों के आयोजन के लिए कार्य किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अभी

तक हुए राष्ट्रीय खेलों से बेहतर हो।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खेलों की अच्छी व्यवस्था के साथ ही खिलाड़ियों और देश भर से आने वाले लोगों के लिए उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेल के आयोजन से यहां के लोगों का मनोबल और प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से एक अच्छा मंच मिलेगा। हमारे उदीयमान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा एवं स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित थे।

दुर्गा पूजा पंडाल में भड़क गयी अभिनेत्री काजोल

जूते पहनकर घुसने वालों को सुनाई खरी-खोटी

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में काजोल को गुस्साते हुए देखा जा रहा है। किसी की ओर इशारा करते हुए अभिनेत्री ने चिल्लाते हुए कहा, 'साइड हो जाए, आपने जूते पहने हैं। कृपया जूते न पहनें।

एक्ट्रेस काजोल हमेशा दुर्गा पूजा को काफी धूमधाम से मनाती है। वह पांच दिनों तक चलने वाली पूजा को काफी श्रद्धा से मनाती है। इस समय जब दुर्गा पूजा चल रही तो काजोल पूजा उत्सव में व्यस्त हैं। सांताक्रूज में नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा की अभिनेत्री काजोल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ताजा वीडियो में काजोल को भड़ते हुए देखा जा रहा हैं। काजोल को जूते पहनकर पंडाल में घुसने वाले आगंतुकों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए भी कैमरे में कैद किया गया। जूते में लोगों को देखकर काजोल गुस्साई और रहा कि वह दुर्गा पूजा का सम्मान करें।

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में काजोल को गुस्साते हुए देखा जा रहा है। किसी की ओर इशारा करते हुए अभिनेत्री ने चिल्लाते हुए कहा, 'साइड हो जाए, आपने जूते पहने हैं। कृपया जूते न पहनें। जो भी जूते पहने हुए हैं, कृपया किनारे हट जाएं। आप सभी कृपया सम्मान करें, यह पूजा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने पीछे खड़े लोगों को संबोधित करते हुए काजोल ने कहा, 'कृपया खुद को बैरिकेड से न टकराएं क्योंकि इससे चोट लगने की संभावना है।

जब काजोल अपना आपा खो बैठीं, तो उनकी अभिनेत्री बहन तनिषा मुखर्जी और अभिनेत्री आलिया भट्ट भी पास में ही मौजूद थीं। काजोल द्वारा जूते पहने लोगों पर चिल्लाने के तुरंत बाद, तनिषा को आलिया से कहते हुए देखा जा सकता है, 'अब तो मुझे भी डर लग रहा है।'

आज सुबह काजोल को अपने अभिनेता पति अजय देवगन और बेटे युग के साथ पंडाल में देखा गया। गुरुवार को, वह हर साल की तरह युग के साथ भक्तों को भोग परोसती नजर आईं। हर साल दुर्गा पूजा पर, काजोल प्रशंसकों को अपने पारिवारिक उत्सवों की एक झलक दिखाती हैं। इससे पहले मुंबई में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान गुरुवार को काजोल को पपराज़ी पर गुस्सा करते हुए देखा गया था। बॉलीवुड अभिनेत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें वह कैमरे से नाराज़ नज़र आ रही थीं। देखें कि उन्होंने क्या कहा और क्यों वह अपना आपा खो बैठीं। इस बीच, वर्क फ्रंट की बात करें तो काजोल कृति सेनन के साथ अपनी फिल्म दो पत्ती की रिलीज के लिए तैयार हैं। फिल्म का निर्देशन शशांक चतुर्वेदी ने किया है और इसे कनिका ढिल्लों ने लिखा है। यह 25 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

कांतारा अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने जाहिर की ख्वाहिश

अगर बेहतर मौका मिला तो हिंदी फिल्मों में काम करूंगा

कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी जिन्होंने 2022 में अपनी फिल्म कंतारा से तहलका मचा दिया था। वह राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करके बेहद खुश हैं। 27 सितंबर को अबू धाबी में IIFA उत्सव में भाग लेने वाले अन्य सितारों में शामिल अभिनेता ने जीत के पीछे की अपनी भावनाओं को साझा किया।

कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी जिन्होंने 2022 में अपनी फिल्म कंतारा से तहलका मचा दिया था। वह राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करके बेहद खुश हैं। 27 सितंबर को अबू धाबी में IIFA उत्सव में भाग लेने वाले अन्य सितारों में शामिल अभिनेता ने जीत के पीछे की अपनी भावनाओं को साझा किया और बताया कि कैसे इसने उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कंतारा में अपने प्रदर्शन के लिए ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। 'कांतारा' फिल्म के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने कहा कि कन्नड़ फिल्म जगत उनकी प्राथमिकता है, लेकिन अगर उन्हें सही मौका मिला तो वह हिंदी फिल्म में काम करना चाहेंगे। शेट्टी ने 2022 की एक्शन थ्रिलर 'कांतारा' के लिए देश भर में लोकप्रियता हासिल की। उन्हें इस लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब भी मिला। उन्होंने कहा कि भाषाई बाधा अब अतीत की बात हो गई है।

शेट्टी ने को यहां आइफा पुरस्कार समारोह में कहा, मेरी प्राथमिकता कन्नड़ फिल्म जगत है। इसने मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया है। आज कोई भाषाई बाधा नहीं है और लोग यहां आपके काम को पहचानते हैं। बदलाव की बदौलत अब यह भारतीय सिनेमा बन गया है। अगर अच्छा अवसर मिला तो मैं (हिंदी फिल्मों में) काम करूंगा।" हाल ही में एक साक्षात्कार में बॉलीवुड द्वारा भारत को नकारात्मक रूप में चित्रित करने के बारे में उनकी कथित टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, अभिनेता-फिल्म निर्माता ने कहा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था उसे गलत समझा गया। मैं (इस बारे में) किसी और दिन स्पष्ट करूंगा। अभिनेता ने आगे बताया कि कंतारा 2 की शूटिंग अभी चल रही है। कन्नड़ अभिनेता ने IIFA उत्सव में कन्नड़ सिनेमा में उत्कृष्ट उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार भी जीता। काम के मोर्चे पर, ऋषभ शेट्टी अपनी आगामी फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो 2022 की हिट फिल्म का प्रीक्वल है।

शनाया कपूर

बॉलीवुड डेब्यू का इंतजार खत्म, विक्रांत के साथ इस फिल्म से मचाएंगी धमाल

संजय कपूर की 24 वर्षीय बेटी शनाया कपूर बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। कथित तौर पर वह फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' में विक्रांत मैसी के साथ अभिनय करेंगी। रिपोर्ट की मानें तो फिल्म में शनाया कपूर एक थिएटर आर्टिस्ट की भूमिका निभाएंगी जबकि विक्रांत मैसी (37) एक दृष्टिहीन संगीतकार के किरदार में होंगे। कहानी उनके प्रेम और आत्म-खोज की परिवर्तनकारी यात्रा के इर्द-गिर्द घूमेगी। इसे 2025 के मध्य में रिलीज करने का लक्ष्य है। 'आंखों की गुस्ताखियां' कथित तौर पर प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड की लोकप्रिय लघु कहानी 'द आइज हैव इट' पर आधारित है। फिल्म करुणा, इच्छाशक्ति, स्वतंत्रता, इच्छा, धारणा, स्मृति और आत्मविश्वास के विषयों का पता लगाएगी। यह संगीत मय पृष्ठभूमि पर आधारित शानदार उतार-चढ़ाव से भरी एक आकर्षक कहानी होने का वादा करती है।

'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल', 'अपहरण और रणनीतिः बालाकोट एंड बियॉन्ड' जैसे वेब शो के निर्देशन के लिए जाने जाने वाले संतोष सिंह कथित तौर पर 'आंखों की गुस्ताखियां' का निर्देशन करेंगे। पटकथा को निरंजन अयंगर और मानसी बागला ने रूपांतरित किया है। शुरुआत में अयंगर को फिल्म का निर्देशन करना था, लेकिन ऐसी फिल्मों को संभालने में व्यापक अनुभव के कारण कथित तौर पर सिंह द्वारा उनकी जगह ले ली गई। रिपोर्ट तो यह भी है कि फिल्म में शनाया कपूर को फाइनल करने से पहले निर्माता कथित तौर पर तारा सुतारिया, अलाया एफ और प्रतिभा रांटा के साथ चर्चा कर रहे थे।

यह अपडेट शनाया कपूर के बॉलीवुड लॉन्च के लंबे इंतजार के बाद आया है। प्रारंभ में, उन्हें करण जौहर द्वारा शशांक खेतान की शहरी ट्रायएंगल प्रेम कहानी 'बेधड़क' में पेश किया जाना था, लेकिन इसे बंद कर दिया गया। दूसरी ओर, विक्रांत मैसी अपनी आगामी फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' की रिलीज के लिए कमर कस रहे हैं।

कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू

अभिनेत्री मदालसा शर्मा ने अपने शो 'अनुपमा' को अलविदा कह दिया है। इस शो में वह काव्या का किरदार निभा रही थीं। हाल ही में मदालसा शर्मा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का शिकार होने की बात कही। मदालसा ने कहा कि सिनेमा की दुनिया में कई कलाकारों को दबाव का सामना करना पड़ता है। खासकर तब, जब वो सिनेमा की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत करते हैं।

मदालसा ने अपने साथ हुए इस घटना के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'लोग बहुत ही सामान्य थे। उनको लगता था कि इस बारे बात कर सकते हैं। इसका पहला उदाहरण है कि अगर कोई बड़ा निर्माता या निर्देशक आपके साथ मीटिंग कर रहा है तो पहला सवाल आता है कि शाम को क्या कर रही हो? डिनर पर मिलते हैं। जब मैंने इस करियर में शुरुआत की तो पता लगा कि यह सब कैसे शुरू होता है। मेरी मीटिंग अच्छी रही थी, इसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि डिनर पर मिलते हैं और एक दूसरे को जानते हैं'। मुझे मालूम था कि इस तरह की मीटिंग ठीक नहीं रहती हैं, तो अपने अनुभव और अपनी मां की वजह से मैं इसका शिकार होने से बच गई।

डबरा में लक्ष्मीनारायण मंदिर में हुआ सवा लाख हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में।

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

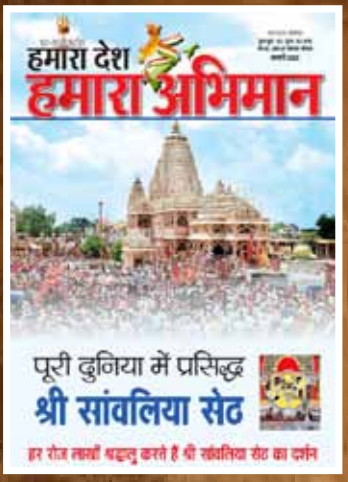

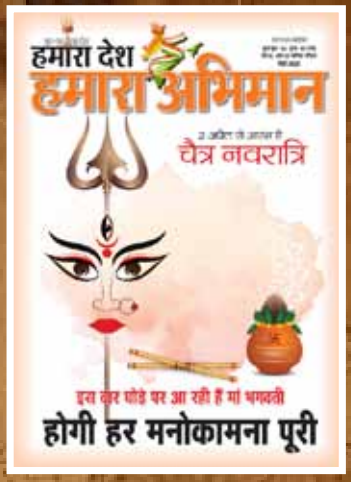

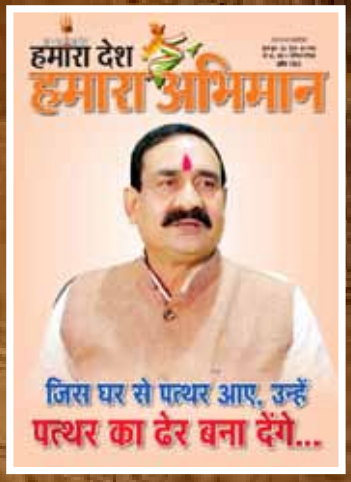

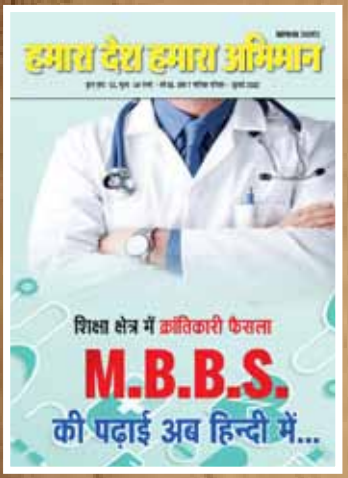

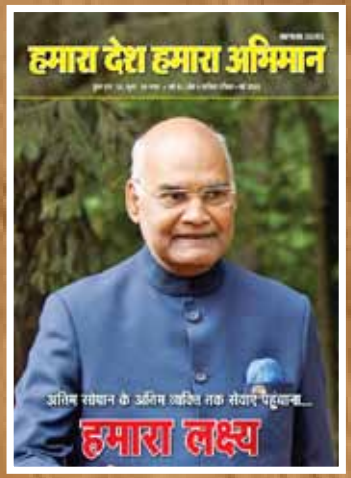

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136